mediaauditornews@gmail.com mediaauditor Epaperdainikmediaauditor.in mediaauditor वर्ष-28 अंक-326 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

रीवा

27 नवंबर 2024 बुधवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

रीवा, सतना से एक साथ प्रकाशित

ऋषभ पंत की सैलरी...

@ पेज 7

अब मैथिली और संस्कृत में भी पढ़ सकेंगे संविधान

● राष्ट्रपति ने किया विमोचन,पीएम मोदी-राहुल गांधी भी रहे मौजूद ● 2004 में अटल सरकार में मिला था आधिकारिक भाषा का दर्जा

नई दिल्ली/पटना (एजेंसी)। अगर आप संस्कृत या मैथिली भाषा में संविधान पढ़ना चाहते हैं तो अब आपकी ये इच्छी पूरी हो जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के मौके पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी कीं।

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। यह मैथिली भाषा के लिए एक बड़ा कदम है, जिसे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया था। संविधान दिवस के मौके पर आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैथिली और संस्कृत भाषा में संविधान की प्रतियों का विमोचन किया।

यह कार्यक्रम संविधान निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। मैथिली भाषा में संविधान का अनुवाद एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

संक्षिप्त समाचार

जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश के चुनावों में बैलेट पेपर के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और पीबी वराले की बेंच ने टिप्पणी की, जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती

है। जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज की गई इस याचिका में बैलेट पेपर से वोटिंग के अलावा कई अन्य दिशा-निर्देशों की मांग की गई थी। इसमें चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर कोई कैंडीडेट इलेक्शन के दौरान वोटर्स को पैसे, शराब बांटने का दोषी पाया जाता है तो अयोग्य घोषित होगा।

दिल्ली में सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी बीजेपी!

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र के नतीजों के बाद दिल्ली में भी बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कम ही वक्त बाकी है और पार्टी की ओर से अलग-अलग रणनीति तैयार की जा रही है।

एक ओर जहां दिल्ली में महाराष्ट्र वाले फॉर्मूले को लागू करने की चर्चा है जिसमें लाडली बहना योजना जैसी स्कीम शामिल है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना ही मैदान में उतर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव प्रचार में सफल रणनीति बनाएगा।

अपराधियों की कुर्क संपत्ति पीड़ितों में बांटेंगी यूपी सरकार

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों से कुर्की के जरिए अर्जित संपत्ति और आय को जब्त कर पीड़ितों में बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डीजीपी ने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, और पुलिस कमिश्नरों को इस संबंध में एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दी है। इस निर्देश के अनुसार, माफिया और अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति पुलिस

जब्त करेगी। जब्त की गई संपत्ति को अदालत के आदेश पर कुर्क किया जाएगा। कुर्की से मिलने वाली आय को पीड़ितों में वितरित किया जाएगा। आदेश के अनुसार, संबंधित जिले के डीएम 2 महीने के भीतर जब्त संपत्ति की नीलामी करेंगे और उससे प्राप्त आय को अपराध से प्रभावित लोगों में बांटेंगे। जानकारी के मुताबिक, अब गैंगस्टर ऐक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लाड्रिंग ऐक्ट के बिना भी पुलिस काली कमाई जब्त या कुर्क कर सकेगी। अपराध से जुड़ी या जुटाई गई संपत्ति के अधिग्रहण या कुर्की का अधिकार मिल गया है।

बैलेट पेपर से चुनाव के लिए अभियान चलाएगी कांग्रेस

देशव्यापी अभियान चलाने के लिए पार्टी ने कर दिया ऐलान

खरगे ने कहा-हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही हो 'चुनाव'

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ा यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खरगे ने कहा, मैं एक बात कहूंगा कि पूरी शक्ति लगाकर ओबीसी, एससी, एसटी और कमजोर तबके के लोग जो वोट दे रहे हैं, वह फिजूल जा रहा है। हमारा कहना है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वे वहां ले जाकर मशीनों को रख दें। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वे कहां खड़े हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा, 'मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की तरह पूरे देश में अभियान चलाएंगे।' इस दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं। लेकिन उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि समाज का हर तबका अपनी हिस्सेदारी चाहता है और उसे मांग रहा है। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में आप देश में एकता चाहते हैं तो फिर नफरत फैलाना बंद करना होगा।

यही नहीं संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खरगे ने यह मांग भी उठाई कि दो दिन संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी और उसकी रक्षा कैसे होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी।

वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन रुका

रियासी (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध सरकार से बातचीत और गवर्नर के आश्वासन के बाद थम गया है। प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे खच्चर और पालकीवालों से मंगलवार को लोकल गवर्नमेंट ने बातचीत कर राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आश्वासन दिया।

रियासी के डिप्टी कमिश्नर विनेश महाजन ने विरोध कर रहे लोगों से कहा कि उनकी चिंताए सुनी जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद खच्चर और पालकीवालों ने 15 दिसंबर तक अपना प्रोटेस्ट निलंबित कर दिया। बातचीत में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले 22 नवंबर से शुरू दुकानदारों, खच्चर और पालकीवालों की हड़ताल और विरोध ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी।

जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा

कांग्रेस के कार्यक्रम में माइक बंद होने पर बोले राहुल गांधी

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी, वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रहे संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15 फीसदी दलित हैं, 15 फीसदी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। 90 फीसदी हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आई है। राहुल ने कहा कि जो भी इस देश में 3 हजार साल से दलितों की, आदिवासियों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है।

सरकार सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहती है

राहुल बोले कि आपके सामने दीवार खड़ी है। आपके सामने दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। पहले सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे। आज दलित को आदिवासी को किसानो को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपकी जेब से निकल जाते हैं।

जाति जनगणना के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे- नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस दिन हमारी सरकार के हाथ ये डेटा आएगा, विकास करने का तरीका बदल जाएगा। विकास की सोच की बुनियाद बनेगी। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है।

मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा गौतम अडाणी रिश्वत केस

मुंबई (एजेंसी)। अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोप का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गृह मंत्रालय को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की गई है। एडवोकेट और देसिया मक्कल शक्ति काची के प्रसिडेंट एमएल रवि ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है। याचिका के माध्यम से उन्होंने कहा कि अडाणी को तमिलनाडु सहित कई भारतीय राज्यों के व्यवसायियों, बिजली वितरण कंपनियों और भारतीय संस्थाओं के साथ सोलर पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। एडवोकेट ने तर्क दिया कि विदेशी देश ने भारत में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसके बाद अभी भी भारतीय जांच एजेंसियां चुप हैं। वह केवल दर्शकों की तरह काम कर रही हैं, जो पूरे देश और 140 करोड़ नागरिकों का अपमान है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार ने सरकारी संस्थान में जनता के विश्वास को खत्म कर दिया है और देश के विकास में बाधा उत्पन्न की है। 24 नवंबर को इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई थी याचिका इससे पहले रविवार यानी 24 नवंबर को एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस मामले की जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के आदेश और यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत ने अडाणी ग्रुप की गड़बड़ियों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि देश के हित में भारतीय एजेंसियों की ओर से भी इस मामले की जांच की जानी चाहिए। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग के लिए भी एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अडाणी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट इन सब खबरों के बीच अडाणी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। अडाणी ग्रीन एनर्जी का शेयर सबसे ज्यादा 6.35 फीसदी गिरा हुआ है। वहीं, अडाणी एंटरप्राइजेज में 2.74 फीसदी और अडाणी पोर्ट्स में 2.27 फीसदी की गिरावट है।

● गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग

● सुप्रीम कोर्ट में भी लगी है याचिका

बड़बोले संजय राउत को पूर्व सीजेआई का करारा जवाब

गिनवा कर दी बड़े फैसलों की फेहरिश्त, खामियां भी बताईं

मुंबई (एजेंसी)। चंद्रचूड़ साहब को इतिहास माफ नहीं करेगा, महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद संजय राउत ने पूर्व चीफ जस्टिस की विधायकों की अयोग्यता का मामला लटकाने का आरोप लगाया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यूबीटी नेता संजय राउत को ऐसे बड़े मुद्दे गिनवा दिए, जिस पर फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा था। एक इंटरव्यू में पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने नौ बेंच की खंडपीठ और सात बेंच वाली पीठ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि क्या किसी पार्टी या व्यक्ति तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट को किस मामले की सुनवाई करनी चाहिए। माफ कीजिएगा, यह अधिकार चीफ जस्टिस के पास है। सांसद संजय राउत ने हार का ठीकरा पूर्व मुख्य जस्टिस के सिर फोड़ने की कोशिश की।

कोर्ट के पास सीमित मैनपावर, बैलेंस बनाना जरूरी होगा

बता दें कि 2022 में एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शिंदे गुट ने भी इस केस में जवाबी याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फैसला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया, जिन्होंने शिंदे गुट को 'असली' शिवसेना घोषित किया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिस पर फैसला नहीं हो सका और शिंदे सरकार का कार्यकाल भी खत्म हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 20 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले लंबित पड़े हैं।

अयोध्या के मिल्कीपुर में जनवरी में हो सकता है उपचुनाव

लखनऊ (एजेंसी)। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सोमवार को भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने याचिका वापस लेने को मंजूरी दी। गोरखनाथ ने कहा कि सपा चुनाव लटकाना चाहती थी। इसलिए कोर्ट में

वकील खड़े किए थे। ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए, सपा के झूठ का पर्दाफाश भी हो जाएगा। गोरखनाथ और निर्दलीय उम्मीदवार शिवमूर्ति ने 15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अर्जी लगाई थी। कहा था कि वे अब यह केस नहीं लड़ना चाहते। यह मामला 2022 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अवधेश प्रसाद ने चुनाव प्रक्रिया में गलत हलफनामा दाखिल किया।

पाकिस्तान की राजधानी में गृहयुद्ध जैसे हालात

● सेना और हजारों इमरान समर्थकों में खूनी संघर्ष,6 सुरक्षाकर्मियों की मौत

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पार्टी के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे पीटीआई के लोग सुरक्षाबलों से भिड़ गए हैं। हिंसा में सुरक्षाबलों के छह जवानों की मौत हो गई है। वहीं पीटीआई के भी दो लोगों की मौत की बात सामने आई है। हिंसा के बीच इमरान खान की बीवी बुशरा अपने 'प्रण' को पूरा करते हुए इस्लामाबाद के डी-चौक तक पहुंच गई हैं। डी-चौक पर पीटीआई के लोगों ने कब्जा जमा लिया है। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने बल प्रयोग किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद इस्लामाबाद में सेना को उतार दिया गया है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिकत 'उपद्रवियों' से निपटने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत सेना तैनात की गई है। बताया गया है कि प्रदर्शनकारियों के आक्रामक होने के बाद सेना बुलाई गई है।

संक्षिप्त समाचार

पावर जनरेटिंग कंपनी के 53 कनिष्ठ अभियंताओं ने लिया एनपीटीआई से प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई) शिवपुरी के निदेशक डा. चित्ताशोक भट्टाचार्य ने कहा कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं को सैद्धांतिक व व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया गया है। अब ये किसी भी विद्युत गृह में कार्य करने के लिए पूर्णत: सक्षम हैं। चित्ताशोक भट्टाचार्य ने यह बात मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के विद्युत गृहों में चयनित 53 कनिष्ठ अभियंताओं के प्रशिक्षण समापन समारोह में कही। पॉवर जनरेटिंग कंपनी के 53 प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं को विद्युत गृहों में तैनात करने से पूर्व एनपीटीआई में 6 सप्ताह के सैद्धांतिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व सी एन्ड आई के इन 53 प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं ने पिछले दिनों नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एनपीटीआई) शि?वपुरी से 6 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलातपूर्वक पूर्ण कर लिया। एनपीटीआई शिवपुरी में पॉवर जनरेटिंग कंपनी की ओर से अधीक्षण अभियंता ट्रेनिंग डॉ. अशोक तिवारी व कार्मिक अधिकारी वर्तिका गुरबानी ने कंपनी की नीति, विजन व मिशन की जानकारी प्रशिक्षु कनिष्ठ अभियंताओं को दी। कार्मिक अधिकारी ने प्रशिक्षुओं को पॉवर जनरेटिंग कंपनी की संगठनात्मक संरचना की जानकारी दी और एनपीटीआई के प्रशिक्षण का फीडबैक लिया।

किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन देने की समुचित व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा है कि किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद श्री फेज तीन हार्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 5 हजार 503, चार माह के लिए 7 हजार 225 एवं पांच माह के लिए 8 हजार 946 रूपये देय होंगे। पाँच हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 8 हजार 946, चार माह के लिए 11 हजार 814 एवं पाँच माह के लिए 14 हजार 683 रूपये देने होंगे। साढे सात से आठ हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु तीन माह के लिए 14 हजार 109, चार माह के लिए 18 हजार 699 एवं पाँच माह के लिए 23 हजार 289 रूपये देय होंगे। श्री फेज दस हार्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए 17 हजार 552 रूपये, चार माह के लिए 23 हजार 289 रूपये एवं पाँच माह के लिए 29 हजार 26 रूपये देय होंगे। कंपनी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 4 अप्रैल 2024 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन दिये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा। उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थाई कनेक्शन के लिए बिल राशि का भुगतान अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से ही करें एवं भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। अस्थाई कनेक्शनों की दरों के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता कंपनी के काल सेन्टर 1912, वेबसाइट अथवा नजदीकी बिजली कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। सरल संयोजन पोर्टल से ऑनलाइन बिजली कनेक्शन लेना आसान

कंपनी कार्यक्षेत्र में अब तक 1 लाख 90 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लिया कनेक्शन

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से भोपाल शहर में घरेलू, गैर घरेलू तथा अस्थाई श्रेणी के लगभग 1 लाख 90 हजार से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को घर बैठे ही नवीन कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु सरल और सुविधाजनक तरीके से त्वरित नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बताया है कि कंपनी के पोर्टल पर आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में तत्काल नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। नये कनेक्शन लेने के लिए बिजली कंपनी के पोर्टल अथवा एप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज अपलोड कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर आनलाइन शुल्क जमा करने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन आवेदन एवं भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत उपभोक्ता को एक एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति मिलते ही बिजली कंपनी द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर विधिवत किए गए आनलाइन आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कंपनी की ओर से स्टेप बाई स्टेप कंफर्मेशन दिया जाएगा। बिजली कर्मचारी द्वारा सर्वे करने के बाद लाइनमेन नये कनेक्शन के लिए मीटर लेकर उपभोक्ता के परिसर में पहुँच जाएगा। आनलाइन आवेदन में बिजली खंभे से उपभोक्ता के परिसर में स्थापित होने वाले मीटर की दूरी तक सर्विस केबल लगाने की सुविधा सशुल्क मुहैया कराई जाएगी।

संविधान के संरक्षक भारत के लोग-राज्यपाल

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होने के अवसर पर प्रदेशवासियों का आवाहन किया है कि संविधान दिवस पर अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्यनिष्ठा के साथ दोहराएं। संकल्प करे कि नागरिक अपने आचरण और व्यवहार से संविधान से प्राप्त अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के पालन के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने में सक्रिय योगदान देंगे। राज्यपाल श्री पटेल राज्य शासन द्वारा आयोजित संविधान प्रस्तावना के सामूहिक वाचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राजनेताओं, अधिकारियों और नागरिकों को हंस ध्वनि सभागार, रवीन्द्र भवन में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कार्यक्रम में सहभागी जनों को संविधान प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा निर्मित वृत्त चित्र ग्लोरी ऑफ कंस्टीटूशन और प्रदेश के संसदीय कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संविधान हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायक जीवंत दस्तावेज और स्वतंत्र भारत का आधुनिक धर्मग्रंथ है, जो हम सबका मार्गदर्शक है। संविधान को देश के हर नागरिक ने अंगीकृत किया है, इसलिए

संविधान के वास्तविक संरक्षक, हम भारत के लोग ही है। उन्होंने कहा कि संविधान किसी एक का नहीं, बल्कि सभी का संरक्षक है। इसलिए उसके संरक्षण और संवर्धन की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। संविधान, जहाँ एक ओर नागरिकों को सशक्त करता है, वही दूसरी ओर नागरिक भी अपने आचरण, व्यवहार से संविधान का समर्थन और संरक्षण करते है। इसलिए जरूरी है कि देश का प्रत्येक नागरिक समर्पित भाव से संविधान के उद्देश्यों, महत्व को समझे और समुचित पालन के द्वारा संविधान के प्रति अपने सम्मान का प्रदर्शन करे। देश के हर वर्ग, हर समुदाय और हर नागरिक का अपने अधिकारों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए सजग और सक्रिय रहना आवश्यक है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व और विश्वव्यापी मूल्यों की समझ का अवसर और उत्सव है। इस महत्वपूर्ण प्रसंग को हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। जरूरी है कि संविधान निर्माताओं द्वारा स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और आत्म-निर्भर राष्ट्र निर्माण के लिए किए गए लम्बे संघर्ष और त्याग के बारे में भावी पीढ़ी को परिचित कराया जाए। संविधान दिवस को केवल शासन और राजनैतिक दलों का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार के उत्सव के रूप में मनाया जाए।

हम सबका दायित्व है कि संविधान के अनुसार जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना, एक सशक्त और समावेशी समाज बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। राज्यपाल श्री पटेल ने संविधान दिवस के पावन प्रसंग पर भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी महान व्यक्तित्वों का पुण्य स्मरण किया। उन्हंत नमन करते हुए कहा कि उनकी अद्भुत दूरदृष्टि और प्रयासों ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है, जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करता है। इसके लिए हम सब उनके प्रति कृतज्ञ है। उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई दी।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने गुजरात पहुंचकर जानी वहां की बिजली व्यवस्था

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में गुजरात के ऊर्जा मंत्री के साथ मंत्रालय में बैठक करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने बैठक में मध्य मध्य प्रदेश में ऊर्जा के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों की जानकारी दी ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है । उन्होंने अटल गृह ज्योति और अटल किसान योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। श्री तोमर ने गुजरात की ऊर्जा नीति के बारे में जानकारी ली।

ऊर्जा मंत्री ने थर्मल पावर स्टेशन गांधीनगर में गुजरात की विद्युत आपूर्ति और तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा भी लगाया। श्री तोमर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण में हम सब महती भूमिका निभाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ और हरित वातावरण में सांस ले सकेंगी।

वेस्ट जोन इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता के तहत पश्चिम क्षेत्रीय प्रतियोगिता के बालिका वर्ग की ब्रास बैंड विधा में मध्यप्रदेश और पाइप बैंड विधा में महाराष्ट्र के दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान पाने वाली ये दोनो टीमें गणतंत्र दिवस-2025 के अवसर पर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में आगामी 24 एवं 25 जनवरी 2025 को पश्चिम का प्रतिनिधित्व करेंगी। मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. संजय गोयल ने विजेता टीमों को पुरूस्कृत किया। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ भोपाल की महापौर श्रीमती

मालती राय और आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सुबह ही किया था। प्रतियोगिता की नोडल अधिकारी सुश्री अर्चना अली ने बताया कि वेस्ट जोन के 6 राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र गोवा एवं केन्द्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव तथा दादर नगर हवेली के विजेता प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसमें ब्रास बैंड विधा में प्रथम स्थान मध्यप्रदेश, द्वितीय स्थान राजस्थान तथा तृतीय स्थान गोवा की टीम ने प्राप्त किया।

सुरखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में शहरों जैसी सुविधाएं होंगी-मंत्री राजपूत

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से सुरखी विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं। हमारा प्रयास है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में शहरों जैसी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हों। विकास का यह क्रम निरंतर चलता रहेगा।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत सागर जिले की सुरखी विधानसभा क्षेत्र के राजा बिलहरा नगर पंचायत के स्थापना दिवस पर आयोजित गौरव दिवस समारोह को

संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकास के लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिलहरा का गौरव दिवस अपने विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है कि तिनका - तिनका जोड़ के हमने गौरव दिवस तक का सफर तय किया है। मंत्री श्री राजपूत ने गौरव दिवस के अवसर पर बिलहरा में 5 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने बिलहरावासियों को बड़ी सौगात देते हुए दो महत्वपूर्ण मार्गों की घोषणा की जिनकी लागत 15 करोड रुपए है। ग्राम सहजपुरीखुर्द तथा 13 मील से सीगना के लिए मार्ग बनेंगे, जिससे लोगों के लिए आवागमन में सुविधा होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हीरा सिंह राजपूत ने कहा कि सुरखी का विकास हमारा संकल्प है। आप लोगों के आशीर्वाद से सुरखी विधानसभा क्षेत्र में यह विकास दिखने लगा है, जिसके परिणाम स्वरुप हम आज बिलहरा में गौरव दिवस मना रहे हैं। विकास का यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा। उल्लेखनीय है कि बिलहरा नगर पंचायत में 4 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्य मंत्री श्री राजपूत द्वारा कराए गए हैं।

मध्यप्रदेश के प्रत्येक ज़िले में नये एडॉप्शन एजेंसी खोली जाएगी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने सोमवार को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता कार्यशाला का शुभारंभ किया। सुश्री भूरिया ने कहा कि यह सर्वविदित है कि बच्चे का सर्वोत्तम विकास परिवार में होता है। भारतीय संस्कृति में परिवार को समाज की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। समस्त संस्कार और गतिविधियां परिवार पर केंद्रित होती है। एक मज़बूत और सुसंस्कृत परिवार ही स्वस्थ समाज के निर्माण का आधार होता है। सुश्री भूरिया ने कहा कि देश में दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल नवंबर के महीने में दत्तक ग्रहण जागरूकता माह मनाया जाता है। ये पहल और इसके सहयोगियों द्वारा आयोजित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क़ानूनी गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पूरे भारत में गोद लेने के महत्व को बढ़ावा देना ,गोद लेने वाले परिवारों की आवश्यकता और बच्चों के जीवन में गोद लेने में सकारात्मक प्रभाव को उजागर करना है। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि जो बच्चे ऑप्शन में तुरंत नहीं जा पाते हैं उन्हें अस्थायी रूप से फ़ॉस्टर केयर में रखा जाता है। फ़ॉस्टर केयर में बच्चों विशेषकर बड़े बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर दिलाना आवश्यक होता है। हमारी कोशिश है कि अधिकतम बच्चों को फोस्टर केयर के माध्यम से परिवार मिल सके। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश एडॉप्शन प्रक्रिया को सरल करने के 12 सुझाव दिए थे इसमें से 6 सुझाव भारत सरकार ने मान्य किए है। इससे प्रक्रिया में काफ़ी सुधार हुआ है। अभी भी लगभग 20 हज़ार से ज़्यादा पेरेंट्स एडॉप्शन के लिए तैयार हैं परंतु केवल 4 हज़ार 500 बच्चे ही गोद दिए जाने के लिए तैयार हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ। समाधान ऑनलाइन में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, जिलों के कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षक सम्मिलित हुए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है अधिकारी-कर्मचारी जनता के प्रति संवेदनशील रहें। जनसमस्याओं के प्रति समर्पित भाव से रुचि लें। जनता के काम का सकारात्मक समाधान होना चाहिए, तभी उनमें संतुष्टि का भाव जागृत होगा। श्री जैन ने कहा कि जनसमस्याओं का निराकरण सत्यता पर आधारित होना चाहिए।

श्री जैन ने कहा कि झूठी रिपोर्टिंग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाकर उनकी सेवाएं समाप्त की जाएं। सीएम हेल्पलाइन का स्वरूप बदलकर फोरक्लोज करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि प्रक्रिया आधारित (प्रोसेस बेस्ड) सिस्टम बनाएं, जिसमें काम का बोझ कम होकर, समय सीमा पर कार्य हो सकेंगे। श्री जैन ने कहा कि अपने अधिकारियों कर्मचारियों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) की जानी चाहिए, उन्हें विश्वास में लेकर कार्य किए जाएं। जिलों में विभागवार जनसमस्याओं का बारीकियों से निदान करें। श्री जैन ने कहा कि अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाए और उनके कार्यों से अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी अवगत कराएं। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सीएम हेल्पलाइन के 20 नवम्बर 2024 तक के विभागवार एवं जिलेवार उच्च प्रदर्शन एवं निम्न प्रदर्शन की जानकारी दी गई। मुख्य सचिव श्री जैन ने सीहोर एवं विदिशा कलेक्टर्स से अच्छा प्रदर्शन होने पर उनसे जानकारी लेकर, इसके अनुरूप कार्य करने के लिए समस्त जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया। मुख्य सचिव श्री जैन ने उच्च प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने के भी निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री जैन ने 10 जिलों उमरिया, शिवपुरी, धार, सिंगरौली, नीमच, राजगढ़, पन्ना, खरगोन, रतलाम, एवं ग्वालियर के शिकायतकर्ताओं से संवाद कर, उनकी शिकायतों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। साथ ही संबंधित जिले के कलेक्टर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

हमीदिया हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक हुई 100वीं कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (एजेंसी)। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने सफलतापूर्वक 100वें कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी ऑपरेशन की उपलब्धि पर चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय टीम को बधाई दी है।उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के प्रयास राज्य के वंचित मरीजों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के हमारे लक्ष्य को और मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

डीन जीएमसी भोपाल

डॉ. कविता सिंह ने बताया कि यह सर्जरी आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई। जो मरीज आयुष्मान योजना के तहत नहीं आते, उनके लिए भी यह सर्जरी मामूली शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. सिंह ने बताया कि बीना के ग्राम माला सानातू की निवासी 54 वर्षीय श्रीमती सरोज रानी पाठक का सफल ऑपरेशन किया गया। उन्हें एक माह पूर्व सीने में दर्द की समस्या पर हमीदिया चिकित्सालय रेफर किया गया। ऐन्जियोग्राफी के दौरान ब्लॉकेज का पता चला। इसके बाद कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग में उनका सफल ऑपरेशन किया गया।

कार्डियोथोरेसिक सर्जरी टीम का नेतृत्व कार्डियक सर्जन डॉ. प्रवीण शर्मा (प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष) और डॉ. ऋषि तिवारी (सहायक प्राध्यापक) ने किया। निश्चेतना विशेषज्ञ डॉ. आर. पी. कौशल (प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष), डॉ. बृजेश कौशल (सह प्राध्यापक), डॉ. श्वेता श्रीवास्तव और डॉ. असीम गार्गेव (सहायक प्राध्यापक), जूनियर डॉक्टरों की टीम में डॉ. धनेश्वरी, डॉ. नितेश, डॉ. हनुमंत, डॉ. अरविंद, डॉ. लीना और डॉ. महेंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परफ्यूजनिस्ट श्री विनय केलकर सहित चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय टीम ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर ने सुनी 130 आवेदकों की समस्याएं निराकरण के दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। नागरिकों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 130 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम तरका से आये शालिक राम गुप्ता ने अपने आवेदन पत्र के माध्यम से बताया कि निःशक्तता का पेंशन न मिलने और दोनों पैर से विकलांग के कारण जीवन यापन करने में समस्याएं आ रही है। संयुक्त कलेक्टर ने शिकायत का तत्काल निराकरण सामाजिक न्याय विभाग से कराया। साथ ही उनकी शारीरिक की स्थिति को देखते हुए ट्राई साइकिल प्रदान कराई। आज समस्या का त्वरित निराकरण होने पर शालिक राम गुप्ता खुश और संतुष्ट दिखे। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रिया पाठक सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।

धौहनी के 38 बीएलओ को कारण बताओ सूचना पत्र जारी

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 82-धौहनी ने 38 बी.एल.ओ. को दिनांक 29.11.2024 तक मतदाताओं का नाम जोड़ने एवं जेन्डर रेशियों, इपिक रेशियो बढ़ाने का लक्ष्य का कार्य पूर्ण करते हुए अपना जबाब निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 82 धौहनी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जबाव समाधान कारक न होने की स्थिति में एक माह के वेतन आहरण पर रोक लगाने की कार्यवाही वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तावित की जावेगी।

उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश 17 अरेरा हिल्स भोपाल के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यॠ म 2025 के दौरान बी. एल. ओ. द्वारा 18-19 वर्ष के मतदाताओं का नाम जोड़ने एवं जेन्डर रेशियो, इपिक रेशियो बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित प्राप्त हुये थे। लगातार निर्देश देने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि मतदान केन्द क्रमांक 6- कोटरो के बीएलओ गनपत सिंह प्रा.शिक्षक, 8-गजरी महिपाल सिंह प्रा. शिक्षक, 26-ताला बाबूलाल कोरी मा. शिक्षक, 29-करमाई विनोद सिंह प्रा. शिक्षक, 31-करमाई राम सिंह प्रा. शिक्षक, 44-भैंसवाही रोमित सिंह शिक्षक, 51-मझौली अजय वर्मा प्रा. शिक्षक, 81-धनिगवां मुनीन्द्र प्रसाद शर्मा स. शिक्षक, 84- बरसेनी जगजीवन सिंह प्रा. शिक्षक, 116- सोनवर्षा शिवप्रसाद साकेत सं.शा. शिक्षक, 126- कमचढ़ राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी प्रा. शिक्षक, 168-गोतरा गणेश प्रसाद साहू शिक्षक, 172-रामपुर अमोल सिंह शिक्षक, 174-टमसार बुद्धलाल सिंह शिक्षक, 176-बड़का डोल कमलेश पाण्डेय शिक्षक, 185-डीम अर्पणा सिंह आ.कार्या., 188-खैरी नारेन्द्र कुमार सिंह शिक्षक, 189-हर्दी हरीलाल अहिरवार शिक्षक, 200-मेड़रा रामकिशोर प्रजापति शिक्षक, 204-कोड़ार कामता प्रसाद टाडिया शिक्षक, 208-सोनगढ़ बैजनाथ जायसवाल शिक्षक, 209-देवरी रामलला जायसवाल शिक्षक, 210-सोनगढ़ योगेन्द्र यादव शिक्षक, 211-मझौली प्रदीप कुमार यादव शिक्षक, 215-घोरबंधा जानकी सिंह उरपेती शिक्षक, 218-अमरोला पवन कुमार पनिका शिक्षक, 221-भरसेंडा श्यामसुन्दर जायसवाल सहा. अध्यापक, 222-भरसेंडा राजकुमार पनिका सहा. अध्यापक, 223-भरसेंडा राजपती पनिका सहा. अध्यापक, 240-कटई सुग्रीव प्रसाद साहू अध्यापक, 245- कोडरिया श्रीमान सिंह सहा. अध्यापक, 277-गड़ईगांव लल्लू प्रसाद पनिका अध्यापक, 279-गडईगांव आशीष कुमार पनिका सहा. अध्यापक, 281-धौहनी विजय बहादुर सिंह सहा. अध्यापक, 282-धौहनी इन्द्रपाल सिंह सहा. अध्यापक, 294-बेलगांव सुमेश्वर प्रसाद जायसवाल सहा. अध्यापक, 295-चमारीडोल राजबहोर साकेत सहा. अध्यापक एवं 296-झारा रामकुशल जायसवाल सहा. अध्यापक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

जिला सलाहकार समिति पी.सी. एवं पी.एन.डी.टी. एक्ट की बैठक आज

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ सुनीता तिवारी ने जानकारी देकर बताया है कि जिला सलाहकार समिति पी.सी. एवं पी. एन. डी. टी. एक्ट जिला सीधी की बैठक दिनांक 27.11.2024 को दोपहर 1.30 बजे से मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई है। उन्होनें सभी संबंधितो को सूचित किया है कि नियत दिनांक, समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संविधान दिवस पर शासकीय सेवकों को दिलाई गई शपथ

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। संविधान दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार सहित जिले के सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में भारत का संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। जिला पंचायत सभागार में संयुक्त कलेक्टर नीलेश शर्मा द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया गया।

इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

शासकीय महाविद्यालय मड़वास में मनाया गया संविधान दिवस

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार शासकीय महाविद्यालय मड़वास में संविधान दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया गया। भारत सरकार ने संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के महत्व को देखते हुए साल भर चलने वाले उत्सव को ''हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान'' अभियान की टैगलाइन के तहत चलाने का निर्णय लिया है। आज इस कार्यॠ म के अंतर्गत सर्वप्रथम संविधान दिवस के महत्व को डॉ. लक्ष्मीकांत कुशवाहा ने बताया। संविधान बनने की प्रि या और लगने वाले समय, उसके महत्व और संविधान में दर्शित सभी मौलिक अधिकारों के बारे में छात्र -छात्राओं को बताया गया।

आज कार्यक्रम के शुरुआत में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गयी फिर संविधान के उद्देशिका का वाचन डॉ.आकांक्षा मिश्रा ने किया और सभी छात्र -छात्राओं एवं स्टॉफ को शपथ दिलाई गयी। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में डॉ. अमिता खरे, डॉ. संध्या वर्मा, डॉ. पूजा गर्ग, डॉ. पंकज मिश्रा ने संविधान के बारे में विभिन्न बारीकियां छात्र -छात्राओं को बतायी। अध्यक्षीय उद्धबोधन प्राचार्य डॉ. आई.पी.प्रजापति ने दिया। उन्होंने संविधान के तहत अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉ संगीता मिश्रा, डॉ निशा सिंह, डॉ. सौरभी गुप्ता, डॉ. ज्योति रजक, डॉ कमलेश जायसवाल, डॉ अनुराग तिवारी, डॉ राजेश पटेल, डॉ सुरेंद्र गुप्ता, धीरज नामदेव शिक्षक, अनिल केवट सहित महाविद्यालय के छात्र/छात्रायें उपस्थित रहे।

समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन दो दिसम्बर से 20 जनवरी तक

किसानों से 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगा धान का उपार्जन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन दो दिसम्बर से किया जाएगा। धान उपार्जन की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। इस संबंध में प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवड़े बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 78 केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं। जिले में 64243 किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। इनका सत्यापन किया जा चुका है। धान उपार्जन के लिए तहसील गुढ़ में 6, जवा में 5, त्योंथर में 19, मनगवां में 10, रायपुर कर्चुलियान में 7, सेमरिया में 8, सिरमौर में 10, तहसील हुजूर में 15 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। अधिकांश गोदाम में ही खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं जिससे उपार्जित धान का तत्काल भण्डारण हो सके।

प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि एफएक्यू धान के लिए 2300 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। धान खरीदी के लिए सभी खरीदी केन्द्रों में तौल कांटे एवं बारदाने उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से धान का उपार्जन किया जाएगा। पंजीकृत किसान अपनी धान बेचने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर से अथवा एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर से दिनांक और समय का निर्धारण करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुकिंग की सुविधा आरंभ हो गई है। धान का उपार्जन करने के लिए खरीदी केन्द्र आते समय किसान असुविधा से बचने के लिए अपने पंजीयन की रसीद, स्लॉट बुकिंग पावती, आधार कार्ड और पंजीकृत मोबाइल अपने साथ रखें। उपार्जन केन्द्र प्रभारी तथा किसान द्वारा बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी सत्यापन के बाद ही खरीदी की पावती जारी होगी। इसे किसान अपने पास सुरक्षित रखें। प्रभारी कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को सभी खरीदी केन्द्रों में उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बंदियों को दिया गया आध्यात्मिक प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। केन्द्रीय जेल रीवा में परिरूद्ध बंदियों को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा 53 बंदियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया । आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षकों नवीन मुखर्जी, राजेश अग्रवाल द्वारा बंदियों को योग, योग निद्रा, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, स्वतः क्रिया आदि के संबंध में प्रशिक्षत कर योग से रोगों का निदान कर शरीर शुद्धि एवं स्वास्थ्य रक्षा हेतु जागरूक किया गया। आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय, उप जेल अधीक्षक संजीव कुमार गेंदले, सहायक जेल अधीक्षक श्याम सिंह कुशवाह, राजेश शुक्ला सहित जेल के बंदी जन व स्टाफ उपस्थित रहा।

एमएलसीटी में सांस्कृतिक एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीवा में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य ने सामाजिक सांस्कृतिक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु डॉ राजकुमार आचार्य उपस्थित रहे।कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के संचालक पुष्पेंद्र त्रिपाठी जी ने किया। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि रीवा महेंद्र तिवारी , थाना प्रभारी विश्विद्यालय हितेंद्रनाथ शर्मा ,सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी राजकिशोर पाण्डेय ,डॉ कमल शुक्ला, वरिष्ठ समाजसेवी विष्णु पाण्डेय,डॉ राजीव पाण्डेय उपस्थित रहे।कार्यक्रम में पधारे सभी अथितियों का स्वागत उद्धबोधन व सम्मान संस्था के संचालक पुष्पेन्द्र त्रिपाठी जी ने किया।कार्यक्रम का संचालन युवा समाजसेवी राजराखन पटेल ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलगुरु डॉ राजकुमार आचार्य जी ने सभी को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा की आज हमारे गौरवशाली संविधान के 75 वर्ष पूरे पूरे हो रहे है। हमारे देश का संविधान बहुत शसक्त और समृद्ध है। देश के संविधान के अनुरूप हम सब आचरण करे । शिक्षा और ज्ञान को अपने तक सीमित न करते हुए इसे व्यापक स्तर तक पहचाने के साथ ही वंचित व पीड़ित वर्ग के लिए कार्य करें तभी आज का दिन सार्थक होगा।महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के बच्चो में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है जिस तरह से आप सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी है उससे ये सिद्ध होता है उन्होंने महाविद्यालय परिवार की प्रसंशा करते हुए कहा कि आप सब से यही आशा और अपेक्षा करते है कि इन बच्चो के अंदर शिक्षा संस्कार के साथ आदर्श नागरिक बनने का भाव विकसित करे जिससे ये बच्चे जहां भी रहे वहां आपके महाविद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता व अपने जिले ,प्रदेश व देश का नाम रोशन करे। विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ ने कहा कि बच्चे सबसे पहले अपने समय की कीमत को पहचाने और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करे ।नशा व अनावश्यक कार्यो से दूर रहे अपने मातापिता की मेहनत को व्यर्थ न जाने दे सही समय मे सही लक्ष्य की ओर बढ़ने का यही समय है। विधायक प्रतिनिधि महेंद्र तिवारी जी ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को बधाई दिया और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिथियों ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का आभार प्रदर्शन संस्था की प्राचार्या डॉ अर्चना पटेल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के ऋषि मिश्रा जी, अब्दुल शहीद खान जी,दीपाली गुप्ता जी,सतेंद्र सर,अनिशा शर्मा,डॉ किरण सिंह,बृजेश पाण्डेय, अजय त्रिपाठी बाबूलाल सहित महाविद्यालय के सभी स्टाफ छात्र छात्राएं उपस्थित रही।

केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों को जैविक खेती एवं मशरूम की खेती के बारे में दिया गया प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। मशरूम उर्जा का एक अच्छा स्त्रोत एवं न्यूनतम कैलोरी भोजन है क्योंकि इसमें पानी अधिक (90 प्रतिशत) शुष्क अवयव कम (10 प्रतिशत) और वसा सबसे कम (0.6 प्रतिशत) है। वसा की कम मात्रा होने के कारण इसे मोटापा रोग, रक्त चाप एवं हृदय रोग के लिये उपयुक्त आहार माना गया है।

सीधी जिले स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में यहाँ के वैज्ञानिक डा. ए.के. श्रीवास्तव, डा. अलका सिंह, डा. शैलेन्द्र सिंह, श्रीमती अमृता तिवारी एवं कृषि महाविद्यालय रीवा की रावे छात्राओं के द्वारा जिले के केन्द्रीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जैविक खेती एवं मशरूम खेती के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रोग्राम में रावे छात्राओ द्वारा बच्चो को जैविक खेती की परिभाषा, उद्देश्य एवं लाभ के बारे में बताया गया। बच्चो को जैविक खेती के अंग जैसे जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, वर्मीकम्पोस्ट एवं दसपर्णी अर्क बनाने की विधि, उपयोग की विधि एवं इनके लाभों के बारे में बताया गया। इसके बाद बच्चो को मशरूम की खेती कैसे करते हैं इसका प्रेक्टिकल करवाया गया। बच्चों को बताया गया कि मशरूम की खेती के लिये गेहूँ का भूसा, पॉलीथीन, मशरूम के बीज एवं कुछ रसायन जैसे कर्बेन्डाजिम एवं फार्मोलिन का उपयोग किया जाता है।

मशरूम की खेती बहुत ही कम खर्च में की जा सकती है एवं इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। मशरूम की खेती बिना खेत वाले किसानों के लिये उपयुक्त होती है। इस प्रोग्राम में कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी वैज्ञानिक, केन्द्रीय विद्यालय के छात्र- छात्रायें, शिक्षक एवं कृषि महाविद्यालय रीवा की रावे छात्रायें भी शामिल हुई।

हम होंगे कामयाब जागरूकता अभियान अंतर्गत जेण्डर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिये ''हम होंगे कामयाब'' जागरूकता अभियान 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। उक्त अभियान अंतर्गत जेंडर संवेदनशीलता और जेंडर-आधारित मुद्दों से निपटने के कलेक्ट्रेट सभागार सीधी में जेण्डर संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में बाल विकास परियोजना सीधी ₹ . 01 एवं ₹ . 02 के परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बाल देखरेख संस्थान के कर्मचारी, वन स्टॉप सेंटर सीधी के अधिकारी/कर्मचारी, शौर्यादल सदस्य, ऊर्जा महिला डेस्क कर्मियों, पैरालीगल वालेन्टियर उपस्थिति में डॉ. दिलीप सोनी सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र कन्या महाविद्यालय जिला सीधी द्वारा जिले में जेंडर संवेदीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया। श्री सोनी द्वारा बताया गया कि मेरे अनुसंधान में देखने को मिला कि हमारे समाज द्वारा ही ज्यादातर भेदभाव प्रदर्शित किये जाते है कि ये लड़की का काम है ये लड़के का। यदि पंचायतों में प%ी प्रधान है तो भी वहां पुरूष को ही काम करने का प्रभार दिया जाता है।

आर.सी. त्रिपाठी जिला कार्यॠ म अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सीधी द्वारा बताया गया कि सेक्स जैवकीय एवं प्राकृतिक होता है जबकि जेण्डर सामाजिक होता है जिसमें कार्य का बटवारा भी जेंडर के आधार पर समाज ही करता है। लड़का या लड़की का पहनावा भी तय किया जाता। समाज में अपने विचारों को बदलकर ही सशक्त किया जाता है। अवधेश सिंह सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास द्वारा मंच संचालन कर बताया गया कि हमारे समाज की विसंगतिया देखी जाती हैं कि प्रापर्टी महिलाओं की अपेक्षा अधिकतर पुरूषों के नाम ही होती है। श्रीमती अरूणिमा पाठक केश वर्कर वन स्टॉप सेंटर सीधी द्वारा घरेलू हिंसा को धाराओं सहित विस्तार पूर्वक बताया गया एवं वन स्टॉप सेंटर में दी गई सेवाये जैसे परामर्श सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थाई आश्रय, 24 घंण्टे हेल्पलाईन सेवा के बारे मे जानकारी दिया गया।

अंत में संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गई एवं 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2024 तक के कार्यॠ म हम होंगे कामयाब अभियान की रूप रेखा का वर्णन किया गया।

विचार

इमरजेंसी लाइट की तरह रोशनी दिखाता संविधान

भारतीय संविधान इमरजेंसी लाइट की तरह है। जब कभी हालात का घना अंधेरा देश के सामने उलझन जैसी स्थिति पैदा करते हैं, संविधान खुद-ब-खुद उजाला बन सामने हाजिर हो जाता है। संविधान के अंजोर में देश को सही राह दिख जाती है। आपातकाल जैसे एक-आध अपवादों को छोड़ दें तो पचहत्तर साल से यह संविधान हमारे लिए रोशनी की लकीर बना हुआ है। देश के सामने जब भी भटकाव जैसे हालात होते हैं, संविधान से ही आगे बढ़ने की राह निकल आती है। भारत को स्वाधीनता देने वाले लॉर्ड एटली सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ब्रिटिश संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन विपक्षी नेता विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि आजाद होते ही भारत बिखर जाएगा और वहां दुष्टों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ चला जाएगा। लेकिन चर्चिल की इस चाहत को स्वाधीन भारत की मनीषा ओर लोकतंत्र ने ध्वस्त कर दिया। दुनिया के विकसित और बड़े माने जाने वाले लोकतंत्रों में भी संवैधानिक व्यवस्था लागू होने या स्वाधीनता के तुरंत बाद समानता के आधार पर वयस्क मतदान का अधिकार नहीं मिला। लेकिन महज 18.33 प्रतिशत साक्षरता वाला देश लोकतंत्र की मजबूत राह पर चल पड़ा। ये सब उपलब्धियां अगर भारतीय लोकतंत्र को हासिल हुई हैं, तो इसकी मजबूत बुनियाद भारतीय संविधान ने रखी। लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद पर भारत राष्ट्र की जो मजबूत इमारत खड़ी हुई है, वह मजबूत संवैधानिक बुनियाद के बिना संभव नहीं हो सकता था। इसी भारतीय संविधान ने 26 नवंबर के दिन 75 साल की यात्रा पूरी कर ली है। 64 लाख रूपए के कुल खर्च और दो साल 11 महीने 18 दिन तक चली बहसों के बाद इसी दिन 1949 में देश ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। इसके ठीक दो महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को देश ने इसे लागू किया और तब से यह हमारी लोकतांत्रिक राष्ट्र यात्रा की आत्मा, धड़कन, रक्त बना हुआ है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को हमने संविधान के निर्माता के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन संविधान के निर्माण में 389 सदस्यों के साथ ही बीएन राव जैसे व्यक्तियों का योगदान कम नहीं रहा। भारत को आजादी देना जब तय हुआ, उसके पहले पंडित नेहरू की अगुआई में एक अंतरिम सरकार बनी। उसी अंतरिम सरकार के मुखिया के नाते जवाहरलाल नेहरू और उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने कर्नाटक के जाने माने विधिवेत्ता बेनेगल नरसिम्ह राव यानी बीएन राव को विधि सलाहकार के पद पर नियुक्त करके संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी थी।

विधानसभा के चुनावों के निहितार्थ

उमेश चतुर्वेदी

हर राज्य की अपनी अहमियत है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो आर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी राज्य का है तो वह महाराष्ट्र है। देश की आर्थिक राजधानी इस राज्य की राजधानी है। आर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के मुकाबले 48 सीटों के साथ दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। राजनीतिक हलकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा विपक्षी निशाने पर रहती है, उस संघ का मुयालय भी इसी राज्य में है।

इस लिहाज से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों का असर दूरगामी होना स्वाभाविक है। मराठी मानुष ने जो जनादेश दिया है, उसका असर देश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही, अर्थनीति पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। देश की राजनीति पर झारखंड के चुनाव नतीजों का भी पड़ना ही है। इसका असर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन की अगुआई राहुल गांधी से छीनने को लेकर आवाज उठने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मांग आ भी गई है कि मोदी को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को दी जाय।

महाराष्ट्र के क्षत्रप शरद पवार को लेकर हाल ही में कहा जाने लगा था कि उनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस धारणा को ढाई साल पहले बीजेपी ने तोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना में टूट हुई और सबसे ज्यादा 104 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता देवेंद्र फणनवीस को शिंदे का सहयोगी बनने के लिए राजी कर लिया। इस सरकार के कार्यकाल में हुआ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुआई वाली महायुति को समर्थन नहीं मिला। बीजेपी और शिवसेना-शिंदे- दोनों को लोकसभा सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सीख ली। बीजेपी ने अपने पारंपरिक गढ़ विदर्भ पर फोकस तो किया ही, गैर मराठा वोटरों पर भी अपना ध्यान लगाया। मराठवाड़ा में शिवसेना शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। नतीजा सामने है। पार्टी ने इस बीच एक काम और किया। उसने माझी लड़की बहीण योजना लागू की। इसके तहत 21 से 65 साल तक की उम्र वाली पात्र महिलाओं को पंद्रह सौ रूपए महीने दिए जाने लगे हैं। राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। इसका फायदा महाराष्ट्र की महायुति सरकार को हुआ है। माना जा रहा है कि राज्य की महिलाओं ने महायुति की अगुआई वाली सरकार को अपना समर्थन दिया है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह कई अन्य राज्य सरकारें महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना शुरू कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इस चलन को और बढ़ावा मिलेगा। बाकी राज्य सरकारें भी तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगी और महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश करेंगी। हालांकि झारखंड में एनडीए का यह फॉर्मूला नहीं चल पाया है। झारखंड की 81 में से 68 सीटों पर पुरूषों की तुलना में साढ़े पांच लाख से ज्यादा महिला वोटरों ने मतदान किया है। बीजेपी वहां के लिए ढाई हजार रूपए की माई सम्मान योजना का प्रस्ताव लेकर आई थी. लेकिन वहां की महिलाओं ने हेमंत सोरेन की गोगो दीदी योजना पर ही ज्यादा भरोसा जताया।

महाराष्ट्र के चुनावों का असर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर बड़ा दल बनने के बाद पार्टी ने ग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। इसके चलते पार्टी में गुरूर दिखने लगा। विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे में पार्टी खुद को सबसे आगे रखने और सहयोगी दलों को पीछे रखने की रणनीति पर काम करने लगी। चुनाव नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह खींचतान सामने आई, उससे साफ था कि कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं था। इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आ रहा है। इसकी तुलना में झारखंड में पार्टी ने हेमंत की सहयोगी की भूमिका में रखा तो वहां के नतीजे अलग तरीके से आए। साफ है कि पार्टी जहां खुद का वर्चस्व रखती है, वहां उसे मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन जहां वह सहयोगी दलों की बैसाखी पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे फायदा होता है। साफ है कि आने वाले दिनों में पार्टी को इस नजरिए से सोचना होगा। महाराष्ट्र के नतीजों से दिल्ली में कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उत्साह में होगी। कांग्रेस जहां उसके साथ जाने का दबाव बना सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी कुछ और मुफ्तिया वादों के साथ मैदान में मजबूती से उतर सकती है।

महाराष्ट्र के चुनावों में असली उत्तराधिकारी कौन का सवाल भी हावी था। शिवसेना को दोनों धड़े हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमे, सभी खुद को ही असली शिवसेना और असली एनसीपी बता रहे थे। इस चुनाव में बेशक अजित पवार के खेमे की सीटें कम हुई हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी से उसके ज्यादा ही विधायक जीते हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीटें बढ़ी हैं, जबकि हिंदुत्ववादी की बजाय सेकुलर चोला धारण करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछड़ गई है। अब इन नतीजों के आधार पर अजित पवार की पार्टी असली एनसीपी होने का दावा करेगी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी खुद को असली और बाला साहब ठाकरे की असल उत्तराधिकारी बताएगी। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। सत्तावादी राजनीति में विधायक लंबे समय तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते। आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का विधायक दल टूटे तो हैरत नहीं होनी चाहिए।

शरद पवार का कहना है कि कटेंगे तो बंटेंगे का असर भी महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा। बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन के खिलाफ राज्य का 11 फीसद मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ। इसकी वजह से हिंदू वोट बैंक महायुति की ओर गोलबंद हुआ। वैसे जानकारों का मानना है कि मराठा आरक्षण की मांग रखने वाले मनोज जरांगे का पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करना और बाद में शरद पवार आदि के दबाव में चुनाव से पैर पीछे खींचना भी महायुति की सफलता की वजह बना। इससे मनोज जरांगे की साख कमजोर हुई और मराठा वोटर महायुति की ओर लौट आया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उससे दूर हो गया था।

महाराष्ट्र के नतीजों से महायुति की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को बिहार की राह पर ले चलना नहीं चाहेगी। ऐसे संकेत उसने दिए भी हैं। यानी वह देवेंद्र फणनवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। इस मसले पर महायुति में तनाव दिख सकता है। जिसे खत्म करने के लिए बीजेपी आलाकमान को ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है।

झारखंड के नतीजों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के गठन के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। हेमंत सोरेन यह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। इन नतीजों ने साबित किया है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झारखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया। झारखंड की कमान बीजेपी की ओर से हिमंत विश्वशर्मा और शिवराज सिंह चौहान को दी गई थी। उत्तर पूर्व से बाहर हिमंत को पार्टी की ओर से पहला असाइनमेंट मिला था। इसमें अगर वे सफल होते तो उनकी राष्ट्रव्यापी छवि बनती। लेकिन वे इसमें नाकाम रहे हैं। अगर बीजेपी को झारखंड में कामयाबी मिलती तो शिवराज का भी कद बढ़ता। लेकिन फिलहाल इसमें ब्रेक लगता दिख रहा है। बीजेपी को चंपई सोरेन के जरिए कोल्हान में चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन चंपई कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसका असर उनके राजनीतिक कद पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की शख्सियत को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, इसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसे आदिवासी सीटों पर समर्थन ना मिलना चिंता का विषय होगा। बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और आदिवासी वोटरों के बीच भरोसा कायम करने के लिए सोचना पड़ेगा।

संभल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से उपजे जटिल सवाल

ललित गर्ग

यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं त्रासद है कि उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर एक सम्प्रदाय विशेष के लोगों ने जो हिंसा, नफरत एवं द्वेष को हथियार बनाकर अशांति फैलायी, वह भारत की एकता, अखण्डता एवं भाईचारे की संस्कृति को क्षति पहुंचाने का माध्यम बनी है। स्थानीय अदालत के आदेश पर एक मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा एवं उन्माद का भड़क उठना और इसके चलते तीन लोगों की जान चले जाना, चुनौतीपूर्ण, विडम्बनापूर्ण एवं शर्मनाक है। इस घटना में कई अन्य लोग घायल भी हुए, जिनमें 30 से अधिक पुलिसकर्मी भी हैं। इस हिंसा को टाला जा सकता था यदि अदालत के आदेश पर हो रहे सर्वेक्षण का हिंसक विरोध नहीं किया जाता। ध्यान रहे कि जब ऐसा होता है तो बैर बढ़ने के साथ देश की छवि पर भी बुरा असर पड़ता है। नि:संदेह इस सम्प्रदाय विशेष को भी यह समझने की आवश्यकता है कि जब देश कई चुनौतियों से दो-चार है, तब राष्ट्रीय एकता एवं सद्भाव को बल देना सबकी पहली और साझी प्राथमिकता बननी चाहिए। एक उन्मादी, विभाजित और वैमनस्यग्रस्त समाज न तो अपना भला कर सकता है और न ही देश को आगे ले जा सकता है। समय आ गया है कि उन मूल कारणों पर विचार किया जाए, जिनके चलते साम्प्रदायिक तनाव, नफरत एवं द्वेष बढ़ाने वाली घटनाएं थम नहीं रही हैं।

संभल की स्थानीय अदालत ने उस याचिका पर जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि मुगल बादशाह बाबर ने इस मस्जिद का निर्माण एक मंदिर के स्थान पर किया था। स्थानीय अदालत के आदेश पर इसी मंगलवार को जब प्रारंभिक सर्वे किया गया था तब भी इलाके में तनाव फैला था, लेकिन उसे दूर कर लिया गया था। समझना कठिन है कि गत दिवस सर्वे के दौरान ऐसे प्रयास क्यों नहीं किए गए जिससे किसी तरह की अव्यवस्था और अशांति न फैलने पाए। रविवार को सर्वे के दौरान जिस तरह पुलिस पर पथराव किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ उन्हें आग के हवाले किया गया, उससे लगता है कि कुछ उन्मादी तत्वों ने उपद्रव की तैयारी कर रखी थी। ऐसी घटनाएं सामाजिक तानेबाने को क्षति पहुंचाने के साथ कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती भी खड़ी करती हैं। यह चिंता की बात है कि यह एक चलन सा बनता जा रहा है कि जब सार्वजनिक स्थलों पर कोई धार्मिक आयोजन होता है, किसी अदालती आदेश पर जांच कार्य होता है तो प्राय: पहले किसी बात को लेकर विवाद होता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। कई बार तो यह हिंसा बड़े पैमाने पर और किसी सुनियोजित साजिश के तहत होती दिखती है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई भीषण हिंसा यही संकेत करती है कि उसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी।

संभल की ताजा घटनाओं के मूल में भड़काऊ नारे एवं संकीर्ण धार्मिकता के मनसूंबे सामने आये हैं। इस तरह की घटनाओं का बार-बार होना अच्छा नहीं है, मंदिर-मस्जिद के एक और मामले ने तनाव की स्थिति उत्पन्न करके शांति एवं सौहार्द को खण्डित किया। यदि मस्जिद पक्ष का यह मानना है कि जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सही नहीं तो उसे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए हिंसा का सहारा लेने का कहीं कोई औचित्य

नहीं और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब निचली अदालत के किसी फैसले के खिलाफ ऊंची अदालतों में जाने का रास्ता खुला हो। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या कुछ राजनीतिक दल एवं सम्प्रदाय विशेष के लोग किसी भी बहाने भड़कने और हिंसा करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं? वास्तव में जैसे यह एक सवाल है कि क्या भारतीय संस्कृति के अस्तित्व एवं अस्मिता से जुड़े इन धार्मिक स्थलों के नाम पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी करना जरूरी समझ लिया गया है? इन प्रश्नों पर संकीर्ण धार्मिकता से परे होकर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए। इसी तरह पुलिस प्रशासन को भी यह देखना होगा कि वैमनस्य बढ़ाने वाली घटनाएं क्यों बढ़ती चली जा रही हैं?

यह सही है कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम किसी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह अधिनियम ऐसे किसी स्थल के सर्वेक्षण की अनुमति भी प्रदान करता है और इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ और धार में भोजशाला परिसर का भी। मथुरा में ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। मंदिर-मस्जिद के विवाद नए नहीं हैं। इन विवादों को सुलझाने की आवश्यकता है। इसका एक तरीका न्यायपालिका का सहारा लेना है और दूसरा आपसी सहमति से विवाद को हल करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि जहां भी ऐसे विवाद हैं, उन्हें दोनों समुदाय आपस में मिल-बैठकर हल करें। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज में सद्भाव, सौहार्द एवं शांति बनी रहेगी। यह समझा जाना चाहिए कि इन दोनों उपायों के अतिरिक्त हिंसा एवं नफरत कोई उपाय नहीं है। इसी के साथ यह भी समझना होगा कि देश को अतीत से अधिक भविष्य की ओर देखने और मंदिर-मस्जिद विवादों से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इससे इन्कार नहीं कि विदेशी आक्रमणकारियों ने अनगिनत मंदिरों का ध्वंस किया। अतीत में हुए इन ज्यादतियों, अत्याचारों एवं विध्वंस घटनाक्रमों को सुधारने की संभावनाएं किसी भी दृष्टि से गलत नहीं कही जा सकती।

देश का चरित्र बनाना है तथा स्वस्थ, सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण समाज की रचना करनी है तो हमें एक ऐसी आचार संहिता को स्वीकार करना होगा जो जीवन में पवित्रता दे। राष्ट्रीय प्रेम व स्वस्थ समाज की रचना की दृष्टि दे एवं कदाचार-संकीर्णता-कट्टरता के इस अंधेरे कुएँ से निकाले। बिना इसके देश का विकास और भौतिक उपलब्धियां बेमानी हैं। व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इरादों की शुद्धता महत्व रखती है, जबकि हमने इसका राजनीतिकरण कर परिणाम को महत्व दे दिया। घटिया उत्पादन के पर्याय के रूप में जाना जाने वाला जापान आज अपनी जीवन शैली को बदल कर उत्कृष्ट उत्पादन का प्रतीक बन विश्वविख्यात हो गया। यह राष्ट्रीय जीवन शैली की पवित्रता का प्रतीक है।

लोकतंत्र की जननी भारत देश का पवित्र ग्रंथ है संविधान

मीडिया ऑडीटर, बैकुंठपुर कोरिया। 75 वे संविधान दिवस के मौके पर कोरिया जिला भाजपा कार्यालय बैकुंठपुर मे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया । जिस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कहा कि देश का संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है। जो लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है। 26 नवंबर के ही दिन संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ। उस दिन हम भारत के लोगों ने एक संविधान को अपनाया और आत्मसात किया। हमारा संविधान हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। संविधान हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों को नमन करता हूं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने संविधान निर्माण का मार्गदर्शन किया। उन्होंने समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान में अंकित की । हम अपने लोकतंत्र के गौरव की इसी भावना के साथ इस विसेष अवसर पर एकत्र हुए हैं. यह अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों को याद करने का भी है। उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद करना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल ने कहा की संविधान दिवस , आजादी का अमृत महोत्सव 26 जनवरी गणतंत्र , 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस , ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बनाते हैं और यह दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम एक साथ हैं । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभूतियों ने आदर्श रेखांकित किया। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व से अखिल भारतीय चेतना को बल मिला ये आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व है। इसमें उल्लिखिति आदर्श एक दूसरे के पूरक हैं । श्री जायसवाल ने बताया की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए अधिनियमों से लोगों को अधिकार मिले हैं। 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। महिला विकास को वास्तविक रूप दिया गया। नारी शक्ति बंदन अधिनियम से महिला सशक्तीकरण का नया युग शुरू हुआ। अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना को मजबूत करने वाले नए कानून बनाए गए। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा की मोदी सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लोगों को प्रगति के अवसर मिल रहे हैं। गरीबों को खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, पक्का घर, राशन मिल रहा है। विश्व स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ बढ़ रहा है ।

भारतीय संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज - लक्ष्मण राजवाड़े : संविधान दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए भाजपा कोरिया जिला उपाध्यक्ष लक्षण राजवाड़े ने कहा की संवैधानिक आदर्शों को अपने व्यवहार में अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करें । उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है । हम सभी इस ऐतिहासिक घटना के भागीदार बने हैं। 75 साल पहले संवैधानिक परिषद ने संवैधानिक परिषद के इसी केंद्र में एक नव स्वतंत्र देश के लिए संविधान बनाने का एक बड़ा कार्य पूरा किया था ।

26 नवंबर 1950 का दिन भारतीय इतिहास के नए युग की शुरुआत का था - महामंत्री पंकज गुप्ता : संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा जिला कोरिया के जिला महामंत्री पंकज गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया की 26 नवंबर, 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी है. इस संविधान ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की. यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान को अपनाया गया था, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला है. अपनी स्थापना के बाद से, संविधान पिछले 75 वर्षों से राष्ट्र की प्रगति को आकार देने वाले मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है । संविधान दिवस के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल , उपाध्यक्ष लक्षण राजवाड़े , अनीता तिवारी , जिला महामंत्री पंकज गुप्ता , विनोद साहू , भानू पाल , अल्प संख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अरशद खान , जिला पंचायत सदस्य वंदना राजवाड़े , सुनीता कुर्रे , महिला मोर्चा जिला महामंत्री संगीता गुप्ता , मंजू जीवनी ,मंडल अध्यक्ष गोपाल राजवाड़े , धीरेन्द्र साहू , कुबेर साहू , प्यारे साहू सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

आयुष्मान कार्ड बनाने शिविर रेडक्रास कार्यालय में आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिले में 70 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने के लिए शहरी क्षेत्र में निःशुल्क शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला ने बताया कि 27 नवम्बर को रेडक्रास सोसायटी कार्यालय झिरिया में शिविर आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त संजय गांधी अस्पताल व जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 70 वर्ष से आयु के वृद्धजनों के कार्ड बनाये जा रहे हैं।

सभी अधिकारी निर्धारित तिथि तक अनिवार्यत: वेतन देयक जनरेट करें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से 27 नवम्बर तक वेतन देयक जनरेट करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी निर्धारित तिथि तक अनिवार्यतः वेतन देयक जनरेट कर दें जिससे एक दिसम्बर को शत-प्रतिशत अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा सके। समय पर वेतन जनरेट न करने पर माह की पहली तारीख को वेतन दिया जाना संभव नहीं होगा। जिन अधिकारियों, कर्मचारियों का वेतन किसी कारणवश रोका गया है, उन्हें छोड़कर शेष सभी के वेतन देयक जनरेट कर दें।

नेशनल लोक अदालत के संबंध में सरपंचों के साथ बैठक आज

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। नेशनल लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 दिसम्बर को किया जाएगा। इस संबंध में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन से पहले जनपद पंचायत रीवा, रायपुर कर्चुलियान तथा गंगेव के ग्राम पंचायतों के सरपंच के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक आगामी 27 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से जिला न्यायालय रीवा के एडीआर सेंटर में होगी।

केन्द्रीय जेल में संविधान दिवस का किया गया आयोजन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। केन्द्रीय जेल रीवा में भारतीय संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर "हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान" के तहत उत्सव के रूप में संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के अवसर पर जेल में स्टॉफ तथा बंदियों को भारतीय संविधान की जानकारी देने के साथ- साथ राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई गई । कार्यक्रम के दौरान जेल में संविधान के प्रति जागरूकता को प्रदर्शित करते हुए बंदियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया । संविधान दिवस के अवसर पर केन्द्रीय जेल रीवा में ए.डी.जे. दिलीप सिंह, सुरेन्द्र सिंह एवं आनंद पाण्डेय उपस्थित रहे। इस दौरान जेल अधीक्षक सतीश कुमार उपाध्याय, संजीव कुमार गेंदले, श्याम सिंह कुशवाह, राजेश शुक्ला, राजीव तिवारी, स्वदीप सिंह, उपेन्द्र द्विवेदी सहित जेल का स्टाफ व बंदी उपस्थित रहे।

हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम पर आयोजित हुआ संविधान दिवस

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। देश के संविधान को स्वीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के आयोजन आज 26 नवम्बर को संविधान दिवस से आरंभ हुए। संविधान दिवस जिले में विकासखण्ड, ग्राम पंचायत स्तर व नगरीय निकायों में समारोह पूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संविधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने कहा कि भारत के संविधान की ही ताकत है कि हम सब एक हैं। हमें मुश्किल समय में संविधान ही राह दिखाता है। यह समन्वय बनाना सिखाता है और इससे आपस में भाई चारा व समानता की राह आसान होती है। उन्होंने सभी को संविधान दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे ने कहा कि स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के अगीकृत होने से स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप सामने आया। संविधान की नीव इतनी मजबूत है कि हमारा देश विश्व में अग्रणी है। समता, स्वतंत्रता, न्याय आदि मूल्यों पर आधारित संविधान के कारण ही हम उत्तरोतर प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मूल्यों को सामने रखकर अपने दायित्व का निर्वहन करें। भारतीय संविधान निर्माताओं का विजन बहुत व्यापक था जिसका परिणाम है कि यह आज भी उसी तरह प्रासंगिक है। इ स अवसर पर विषय विशेषज्ञ अवधेश प्रताप सिंह विश्व विद्यालय के विधि विभाग के प्राध्यापक डॉ. आलोक मिश्रा ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही संविधान की मूलभावना है। संविधान के अनुरूप आचरण करना हमारा स्वाभिमान है। देश की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंधित करने का अधिकार हमारे संविधान में है। कार्यक्रम में संविधान निर्माण व उसके मौलिक उद्देश्यों की जानकारी देने वाली वीडियो क्लिप का प्रसारण इस दौरान किया गया। संविधान की उद्देशिका का वाचन उपस्थित जनों ने किया। इससे पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी जीवेन्द्र सिंह एवं कार्यपालन मंत्री पीएचई संजय पाण्डेय ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने आभार प्रदर्शित किया। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।

नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह पर एसएनसीयू में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

मीडिया ऑडीटर, सीधी (एजेंसी)। जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर एसएनसीयू में जागरूकता का कार्यक्र म रखा गया जिसके अंतर्गत स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई गई। एसएनसीयू को सजाया गयातथा वार्ड में भर्ती बच्चों के अभिभावकों को छोटे बच्चों की देखभाल के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बच्चों को माँ के दूध के महत्व, टीकाकरण, साफसफाई, कंगारु केयर, शिशु की देखभाल आदि की जानकारी प्रदान की गई।

उपरोक्त कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉ दीपा रानी इसरानी, डॉ सुरेंद्र सिंह नेशनल ऐससर, डॉ हरिओम, डॉ विनय, डॉ आशीष, डॉ सोनी, डॉ शोभा एवं अन्य सभी नर्सिंग ऑफिसर्स, सहायक प्रबंधक पंकज सिंह, अन्य पैरामेडिकल स्टाफउपस्थित रहे।

एक एकड़ पर 21 क्विंटल की धान खरीदी का झुठा आश्वासन दें.किसानों के साथ किया जा रहा खिलवाड़

मीडिया ऑडीटर, चिरमिरी (एजेंसी)। पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने अपने समर्थकों के साथ सोमवार को एमसीबी ज़िले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट को किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा.

उपरोक्त ज्ञापन में डॉ. विनय ने बताया कि वर्ष 2023 में भाजपा सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाने की घोषणा अपने घोषणा पत्र में की गई थी, प्रदेश सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21. क्विंटल धान खरीदी नहीं किया की जा रही है जिस जिले के किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, प्रदेश सरकार अपने घोषणा पत्र का पालन नहीं कर रही है जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, प्रति एकड़ 21. क्विंटल 3100.रुपए के हिसाब से करें न किए जाने की दशा में स्थानीय एवं प्रदेश स्तर पर कांग्रेस पार्टी इसका व्यापक विरोध करेगी पूर्व विधायक डॉ विनय जायसवाल ने पत्र के माध्यम से आगे बताया कि प्रदेश सरकार को हम अवगत करा रहे हैं कि अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों का पालन सुनिश्चित करें तथा रकबा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करते हुए प्रति एकड़ 21.क्विंटल धान 3100.की प्रति दर के हिसाब से क्रय कर किसानों को विक्रय मूल्य का भुगतान करें , वहीं जिला कलेक्टर एमसीबी ने पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल को आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही आपके पत्र का अवलोकन कर कार्रवाई की जाएगी ।

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (एजेंसी)। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी श्री संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में संविधान दिवस के अवसर पर दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला न्यायालय परिसर ए.डी.आर. सेन्टर भवन मीटिंग हॉल में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। प्रस्तावना का वाचन श्री वीरेन्द्र जोशी जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा कराया गया। विशेष न्यायाधीश श्रीमती रमा जयंत मित्तल द्वारा सभी को संविधान दिवस की शुभकामना दी गई।

इसके उपरांत ए.डी.आर. सेन्टर में साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजन किया गया। उक्त शिविर में विशेष न्यायाधीश श्रीमती रमा जयंत मित्तल ने मौलिक अधिकार के बारे में बताया और जानकारी दी कि हमारे क्या मौलिक अधिकार है। यह भी बताया कि हमारे मौलिक अधिकार एक सीमा तक सीमित है। उक्त शिविर में अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ सीधी श्री बृजेन्द्र सिंह ने संविधान के प्रावधानों के संबंध में चर्चा की। शिविर में प्रथम जिला न्यायाधीश श्री राजेश श्रीवास्तव ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वीरेन्द्र जोशी ने संविधान के महत्व के साथ-साथ आगामी 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। उक्त शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सोनू जैन ने संविधान में निहित कर्तव्य के बारे में विस्तार से बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सोनम शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्र म का संचालन श्री रमेश द्विवेदी जी द्वारा किया गया।

रोजगार मेला 29 को मऊगंज में

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। मऊगंज जिले में सेठ रधुनाथ प्रसाद महाविद्यालय मऊगंज में 29 नवम्बर को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला मध्यप्रदेश संकल्प योजना के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मेले में 7 कंपनियों एवं नियोजकों द्वारा युवाओं का चयन किया जाएगा। मेले में शामिल होने के लिए विभिन्न कंपनियों हेतु युवक एवं युवतियों की आयु सीमा 18 से 48 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आयु सीमा विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग होगी। वेतन एवं भत्ते 8000 रुपए से 25 हजार रुपए तक निर्धारित किया गया है। युवाओ को अपने साथ मूल अंकसूची तथा निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड या वोटर आईडी, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन एवं नवीनतम दो पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर आना अनिवार्य होगा। उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने बताया कि रोजगार मेले में बोनटन टेक्नोमेक फर्नीचर प्रा. लि. इंदौर, द ई पाई डाट काम (हावेल्स सोलर प्लांट) रीवा, ग्रो फास्ट एग्रोटेक प्रा. लि. रीवा, प्रगतिशील बायोटेक रीवा, प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा, एचडीएफसी लाईफ इश्योरेन्स लि. तथा एसआईएस सिक्युरिटी सर्विसेस सिंगरौली में रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे।

पतंजलि ग्रुप मऊगंज जिले में करेगा पाँच हजार करोड़ रुपए का निवेश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में 23 अक्टूबर को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में विन्ध्य क्षेत्र में औद्योगिक निवेश के कई प्रस्ताव मिले थे। इसमें पतंजलि ग्रुप के आचार्य बालकृष्ण ने सहभागिता निभाई थी। पतंजलि ग्रुप ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को पत्र लिखकर मऊगंज जिले में पाँच हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भेजा है। इसके लिए ग्राम घुरेहटा में 175 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की माँग की गई है। इसमें कृषि पर आधारित औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्रीय संचालक एमपीआईडीसी यूके तिवारी ने बताया कि पतंजलि ग्रुप विन्ध्य क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इसमें फसल विविधीकरण, किसानों के प्रशिक्षण, बीज उत्पादक इकाईयों की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को शामिल किया गया है। इस कार्ययोजना में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के साथ-साथ उनके कौशल उन्नयन और जागरूकता को बढ़ावा देने के आयामों को भी शामिल किया गया है। पतंजलि ग्रुप घुरेहटा में 175 हेक्टेयर भूमि में पाँच हजार करोड़ रुपए का निवेश करके विभिन्न इकाईयों की स्थापना करेगी। इससे लगभग पाँच हजार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कार्ययोजना के लागू होने से मऊगंज जिले में औद्योगीकरण में तेजी आएगी।

कमिश्नर ने आमजनता के आवेदनों में की जन सुनवाई

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय सभागार में कमिश्नर बीएस जामोद ने आमजनता के आवेदनों पर जन सुनवाई की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई के आवेदन पत्रों का तत्परता से निराकरण करें। निराकरण की जानकारी आवेदक को भी अनिवार्य रूप से दें। आवेदन पत्रों के निराकरण का प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में कमिश्नर ने ग्राम गोरगी में नल जल योजना, जल संसाधन विभाग में लंबित पेंशन प्रकरण तथा सीधी जिले में बुड़गोना में सिंचाई के लिए नहर में पानी छोड़ने के आवेदनों की सुनवाई की। जन सुनवाई में सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

छात्राओं द्वारा पार्टीसेपेट्री रूरल अप्रेजल कार्य किया गया

मीडिया ऑडीटर, सीधी (एजेंसी)। कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक डॉ. अलका सिंह, डॉ. शैलेन्द्र सिंह गौतम एवं श्रीमती अमृता तिवारी के मार्गदर्शन में कालेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा की चतुर्थ वर्ष की छात्राओं द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र सीधी में ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव (रावे) के अन्तर्गत पड़रा ग्राम में पार्टीसेपेट्री रूरल अप्रेजल के अन्तर्गत सामाजिक मानचित्रण (सोशल मैपिंग) कार्यक्र म का आयोजन किया गया। इस कार्यक्र म का उद्देश्य सामाजिक संरचना, संसाधनो और आवश्यकताओ को समझना और दर्शाना था ताकि विकास योजनाओ को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इस कार्यक्र म में 11 रावे छात्राओं (दीक्षा सिंह राजपूत, पुष्पांजली पाण्डेय, राखी सोनी, सीमा सिंह, प्रतिक्षा सोनी, अंकिता त्रिपाठी, श्वाती तिवारी, राधा बाघेल, दिव्याशी त्रिपाठी, यशस्वी तिवारी एवं मोनिष्का साक्य) ने भाग लिया जिन्होने गॉव के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और स्थानीय निवासियों एवं किसानों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। छात्राओं ने गॉव के स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, जल स्त्रोत एवं अन्य कार्यालय जैसे कि आगनवाड़ी, आर.टी.ओ. आफिस आदि का मानचित्रण किया। रावे छात्राओ ने बताया कि इस गतिविधि से उन्हे गॉव की सामाजिक स्थिति को समझने का मौका मिला। गॉव की सरपंच श्रीमती अन्जूलता कोल ने छात्राओ की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की गतिविधि हमारे गॉव के विकास में मददगार साबित होगी। इस गतिविधि के अंत में रावे छात्राओं ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें ग्राम की सामाजिक स्थिति, संसाधनों एवं प्रगति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है।

जनसुनवाई में 80 आवेदकों की सुनी गई समस्यायें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्ट्रेट में 80 आवेदकों की समस्यायें सुनीं गई। प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे ने विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर समाधानकारक निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय तथा डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले ने भी जनसुनवाई की।

इस दौरान रीवा निवास उसमान अंसारी को आर्थिक सहायता के तौर पर एक हजार रूपये रेडक्रास सोसायटी से देने के निर्देश दिये गये। जमुना साकेत जोरी निवासी के खाद्यान्न प्रदाय के आवेदन पर खाद्य अधिकारी को तथा पूर्व मा.वि. भौखरी खुर्द में हैण्ड पंप सुधार के आवेदन पर पीएचई विभाग के अधिकारी को कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी कलेक्टर द्वारा दिये गये। शंकुलता निपनिया निवासी के आर्थिक सहायता प्रदान करने, राजमणि यादव चन्द्रपुर सेमरिया निवासी के खसरा खतौनी की नकल के आवेदनों को संबंधित एसडीएम को कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। जबकि भीटा गुढ़ के सुकवरिया के निजी आराजी के अवैध कब्जा हटाने, पुष्पा त्रिपाठी गहनौआ के निजी भूमि में अवैध बोर कर धमकी देने के आवेदनों पर संबंधित पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दरहा चचाई निवासी नरेन्द्र कुमार द्विवेदी ने किसान सम्मान निधि योजना में नाम शामिल कराने का आवेदन दिया। जिसे कार्यवाही हेतु तहसीलदार सेमरिया को प्रेषित किया गया। महेश प्रसाद निगम रीवा ने वृद्धाश्रम में आश्रय देने का आवेदन दिया। प्रभारी कलेक्टर ने सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये। इस दौरान रामकृपाल विश्वकर्मा मडवा के पुत्रों द्वारा उनकी जमीन अवैध तरीके से नामांतरण कराने तथा हरिजन बस्ती भटलों मार्ग से अवरोध हटाने के आवेदन पर संबंधित राजस्व अधिकारियों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। रीवा निवासी नारायण डिगवानी के धारणाधिकार के लंबित प्रकरणों के निराकरण करने, तारादेवी शर्मा गुढ़ के दिव्यांग पुत्र को पेंशन प्रदाय करने के आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी कलेक्टर द्वारा जनसुनवाई में दिये गये।

देश के 10 राज्यों में घना कोहरा

नई दिल्ली/भोपाल (एजेंसी)। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 राज्यों में मंगलवार को घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इससे कई शहरों में विजिबिलिटी भी घट गई है। सबसे कम विजिबिलिटी त्रिपुरा के अगरतला और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्ज की गई। दोनों जगहों पर मंगलवार सुबह पर 50 मीटर से दूर देखना मुश्किल हो रहा था। वहीं, बिहार के पुर्णिया और भागलपुर में विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी अब रुक गई है, लेकिन लाहौल स्पीति और कल्पा इलाके में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहां 4 दिन बाद बर्फबारी हो सकती है। तब तक न्यूनतम तापमान में इससे ज्यादा गिरावट के आसार कम हैं। उधर, मध्य भारत के राज्यों- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठंड का असर कम हो गया है। सिर्फ एमपी के पचमढ़ी में तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। बाकी शहरों में 2 दिन बाद तापमान में और गिरावट हो सकती है। फिलहाल देश में कहीं भी कोल्ड वेव का अलर्ट नहीं है।

पेंड्रा में मालगाड़ी के 23 डिब्बे डिरेल

पेंड्रा (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मंगलवार को कोयला ले जा रही मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन सहित 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भनवारटंक रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। राहत कार्य जारी है। मालगाड़ी के डिब्बे पलटने से ट्रैक पर कोयले का ढेर लग गया है, जिससे इस रूट से गुजरने वाली 6 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं 9 का रूट डायवर्ट किया गया है। हादसे में अप और डाउन दोनों लाइन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। रूट पर यातायात बहाल होने में 2 से अधिक दिन लग सकते हैं। हादसे में ओएचई तार और सिग्नल के खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में रेलवे को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। अप और डाउन दोनों रूट पर आवागमन पूरी तरह से प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे। वहां मालगाड़ी के डिब्बे पलटे पड़े थे। हादसा कैसे हुआ है, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं इस घटना के चलते बिलासपुर-पेंड्रारोड-कटनी रेलवे मार्ग की सभी ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में शहडोल-बिलासपुर मेमू हादसे के बाद से खड़ी है। सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचकर ट्रैक क्लियर करने में जुटे हैं।

भगवान के दर्शन को लेकर उदयपुर के पूर्व-राजघराने में हिंसा

उदयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद आज भी हालात तनावपूर्ण रहे। हालांकि कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। पुलिस ने बेरिकेड्स लगाने के साथ ही भीड़ को रोकने के लिए उसमें लोहे की ऊंची-ऊंची जाली लगाई है। प्रशासन ने विवादित जगह को कुर्क कर रिसीवर की नियुक्ति कर दी।

मोदी बोले- संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा- हमने देश में आपातकाल देखा है। हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का सामना किया है। ये संविधान की ही ताकत है कि आज जम्मू-कश्मीर में बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है। आज पहली बार जम्मू-कश्मीर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं संविधान और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हम यह नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। पीएम ने कहा- जिन लोगों ने इस हमले में अपनी जान गंवाई। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं देश के संकल्प को भी दोहराना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले सभी आतंकवादी संगठनों को करारा जवाब मिलेगा। एक समय था जब वरिष्ठ नागरिकों को

बैंकों में जाकर यह साबित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं। आज वरिष्ठ नागरिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। संविधान की मूल प्रति में भगवान राम, माता सीता की तस्वीरें हैं। भारतीय संस्कृति के प्रतीक चित्र इसलिए हैं ताकि वे हमें मानवीय मूल्यों की याद दिला सकें। ये मानवीय मूल्य आज के भारत की नीतियों और निर्णयों का आधार हैं। संविधान दिवस एक मंच पर दिखे मोदी-राहुल, संविधान अब संस्कृत और मैथिली में भी मंगलवा को ही देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद रहे थे। आयोजन की थीम हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान रखी गई थी।

याचिकाकर्ता ने कहा- ईवीएम नहीं, बैलट से चुनाव हो

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलेक्शन में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम को दोबारा शुरू करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा- ईवीएम से पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है। ऐसे आइडिया कहां से लाते हो। इस पर याचिकाकर्ता केए पॉल ने कहा- चंद्रबाबू नायडू और वाईएस जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए हैं। बेंच ने कहा, चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन

रेड्डी जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ होती है और जब वे जीतते हैं तो वे कुछ नहीं कहते हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं। हम इसे खारिज कर रहे हैं। ये वो जगह नहीं है जहां आप इस सब पर बहस करें। आप इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? आपका कार्य क्षेत्र बहुत अलग है। बता दें कि पॉल ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं, जिसने 3 लाख से अधिक अनाथों और 40 लाख विधवाओं का रेस्क्यू किया है। अमेरिका जैसे देशों में भी बैलेट पेपर से वोटिंग याचिकाकर्ता केए पॉल ने इलॉन मस्क की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जिन्होंने सुझाव दिया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा- मैंने 150 से अधिक देशों का दौरा किया है और अधिकांश ने बैलेट पेपर वोटिंग को अपनाया है।

कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी, वहां जाति जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा, उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15 प्रतिशता दलित, 15त्न अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं, ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50त्न से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90त्न आबादी इन्हीं वर्गों से है। राहुल ने कहा कि जो भी इस देश में 3 हजार साल से दलितों की, आदिवासियों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है।

काफी लोग आए, कहने लगे जाकर बैठ जाइए, मैंने कहा कि मैं खड़ा रहूंगा। मैंने कहा कि माइक जितना ऑफ करना है करो, मैं खड़ा रहूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की तस्वीर है पीछे, वे बोलना चाहते थे, उन्हें चुप करा दिया गया।

महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान नहीं, अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। इसके लिए भाजपा आज या कल पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से रायशुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल आज यानी 26 नवंबर तक ही है। नए मुख्यमंत्री के शपथ की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे ही कार्यवाहक ष्टरूरहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम रहे। शिंदे के इस्तीफे के बाद भाजपा विधायकों की मुंबई में बैठक बुलाई गई है। इसमें फडणवीस को नेता चुना जाएगा। इसके बाद सह्याद्रि गेस्ट हाउस में शिंदे, फडणवीस और अजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नए मुख्यमंत्री के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग

फाइनल हो चुका है। आज ही उनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। फडणवीस के सीएम बनने पर नई सरकार में पहले की ही तरह दो डिप्टी ष्टरूहोंगे। एनसीपी की ओर से अजित पवार और शिवसेना की ओर से शिंदे किसी नए विधायक का नाम आगे कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार का एजेंडा तय करने के लिए तीनों दलों की एक कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके मुखिया एकनाथ शिंदे हो सकते हैं।

लॉरेंस ने चंडीगढ़ के 2 क्लबों के बाहर ब्लास्ट कराया

चंडीगढ़ (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को चंडीगढ़ दौरे से पहले मंगलवार सुबह सेक्टर-26 में 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए। धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गोल्डी बराड़ ने इस बारे में सोशल मीडिया पोस्ट डाली है। उसने धमाके की वजह प्रोटेक्शन मनी न देना बताया है। सेविले बार एंड लाउंज और डि%ओरा क्लब के बाहर हुए धमाके में क्लब के बाहर के शीशे टूट गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेविले बार एंड लाउंज क्लब के मालिकों में मशहूर रैपर बादशाह भी पार्टनर हैं। गोल्डी बराड़ के हवाले वाली सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- %2 ब्लास्ट की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लेते हैं। इन दोनों क्लबों के मालिकों को प्रोटेक्शन मनी के लिए मैसेज किया था। मगर इन्हें हमारी कॉल की घंटी नहीं सुनाई दे रही थी। इनके कान खोलने के लिए यह धमाके किए। जो भी हमारे कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, वह समझ जाएं कि इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है।% वहीं पुलिस की जांच में सामने आया कि बम फेंकने वाले युवक बाइक पर आए थे। वारदात में जो बम इस्तेमाल हुए हैं, उनमें कील और ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ था। मौके पर इससे जुड़ी हुई चीजें भी बरामद हुई हैं। पुलिस मानकर चल रही है कि देसी बम (सुतली बम) फोड़े गए हैं। पुलिस एक्सटॉर्शन एंगल पर भी जांच कर रही है।

पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभातीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने हढ्ढ को दिए इंटरव्यू में कहा- लोकतंत्र में विपक्ष का स्पेस अलग है। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए है। दरअसल, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ज्यूडिशियरी के काम करने के तौर-तरीके पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ज्यूडिशियरी का काम भी विपक्ष ने ले लिया है।

हम मीडिया, जांच एजेंसी और न्यायपालिका का काम कर रहे हैं। राहुल के इसी बयान का जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा- मैं राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों को यह नहीं मानना चाहिए कि न्यायपालिका को संसद या विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। यह गलत धारणा है। इसे बदलना चाहिए।

सीनियर आर्मी अफसर की रिपोर्ट- महिला सीओएस बहुत शिकायती

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने महिला कमांडिंग अफसरों के कामकाज के रिव्यू के बाद कहा कि वे बहुत ज्यादा शिकायत करती हैं। मीडिया में ये रिपोर्ट 26 नवंबर को सामने आई है। दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट को 17 कॉर्प्स में टेन्योर खत्म कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी ने बनाया है, जिसे 1 अक्टूबर को ईस्टर्न कमांड के कमांडर-इन-चीफ को एक खत के रूप में भेजा गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला सीओएस में ईगो प्रॉब्लम रहती है।

वे छोटी-छोटी बात का सेलिब्रेशन करती हैं। जूनियर्स के लिए उनका व्यवहार %टॉक्सिक% रहता है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद आर्मी के भीतर और बाहर चर्चा शुरू हो गई है।

वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन रुका

रियासी (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट का विरोध सरकार से बातचीत और गवर्नर के आश्वासन के बाद थम गया है। लोकल गवर्नमेंट ने विरोध कर रहे खच्चर और पालकीवालों से मंगलवार को बातचीत की। उन्हें राज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से आश्वासन दिया। रियासी के डिप्टी कमिश्नर विनेश महाजन ने विरोध कर रहे लोगों से कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद खच्चर और पालकीवालों ने 15 दिसंबर तक अपना प्रोटेस्ट रोक दिया। बातचीत के दौरान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इससे पहले 22 नवंबर से चल रहे दुकानदारों, खच्चर और पालकीवालों की हड़ताल और विरोध ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया था। पुलिस

ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हिंसक प्रदर्शन में कुछ लोग घायल भी हुए थे।

पीएम मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत-कल्पना

रांची (एजेंसी)। झारखंड में शानदार जीत के बाद जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन दिल्ली के एक दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थीं। भाजपा नेताओं से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा- आशीर्वाद के लिए आए थे।

बहुत सारी बातें हैं। आगे भी मुलाकात होती रहेगी। वहीं, सोरेन ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद कहा- राज्य में शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। नई सरकार बनने जा रही है।

किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में

पटियाला/लुधियाना/जींद (एजेंसी)। हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत (भूख हड़ताल) शुरू करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस उन्हें लुधियाना स्थित डीएमसी अस्पताल ले गई है। कोई व्यक्ति उन तक न पहुंचे, इसके लिए अस्पताल के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। अस्पताल में डल्लेवाल कुछ नहीं खा रहे हैं। उनको हिरासत में लिए जाने के बाद किसान नेता और पूर्व फौजी सुखजीत सिंह हरदो झंडे खनौरी बॉर्डर पर मरणव्रत पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे इस अनशन के दौरान मर जाते हैं तो उनका शव यहीं रहेगा और दूसरा किसान मरणव्रत पर बैठ जाएगा। एक अन्य नेता ने बताया कि डल्लेवाल ठीक हैं। जैसा उन्होंने (डल्लेवाल) कहा था कि वह 26 से

मरणव्रत पर बैठेंगे, उन्होंने लुधियाना में कुछ खाया नहीं है। इस बीच किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। वहीं हरियाणा और पंजाब के सीनियर अधिकारियों की बैठक में सहमति बनी है कि शंभू बॉर्डर का 4 फीट का एरिया खोला जाएगा, ताकि किसान बिना ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के आगे बढ़ सकें। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दी गई है।

डल्लेवाल की हिरासत पर पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि संविधान दिवस पर यह संविधान की हत्या है। मैं खनौरी बॉर्डर मोर्चे पर समर्थन में पहुंच रहा हूं। आप सब भी आइए और केंद्र और पंजाब सरकार के इस जुगलबंदी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। जो किसान, नौजवान शंभू बॉर्डर के नजदीक हैं, वो शंभू बॉर्डर पहुंचे। इससे पहले किसान नेता सरवन पंधेर ने कहा कि सोमवार रात करीब 2 बजे डल्लेवाल को खनौरी बॉर्डर से उठा लिया गया है। उन्हें कहां ले गए हैं, इसकी जानकारी नहीं है। जिन्होंने डल्लेवाल को उठाया है, उनमें कई पुलिसवाले हिंदी भाषा बोल रहे थे। डल्लेवाल को सीएम भगवंत मान के ज्यूरिस्डिक्शन से उठाया गया है, इसलिए पंजाब सरकार को किसानों के प्रति अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। बताना होगा कि उन्हें कहां ले गए हैं? अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इंफाल में आर्मी कैंप में काम करने वाला शख्स लापता

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के पश्चिमी इंफाल में एक 55 साल के शख्स के लापता होने के बाद मंगलवार को इलाके में तनाव बढ़ गया। लापता हुए व्यक्ति की पहचान लैशराम कमलबाबू सिंह के तौर पर की गई है। वह सोमवार दोपहर कांगपोकपी के लीमाखोंग आर्मी कैंप में काम पर रिपोर्ट करने के लिए घर से निकले थे और तब से लापता है। उनका मोबाइल फोन भी बंद है। वे आर्मी कैंप में मैनियल जॉब करते थे। कमलबाबू को ढूंढने के लिए पुलिस और सेना तलाशी अभियान चला रही है। मंगलवार को कमलबाबू को ढूंढने के लिए गांव से बड़ी संख्या में लोग लीमाखोंग जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कांटो सबल के पास ही रोक दिया। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और लोगों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया। 6 मैतेई लोगों की अगवा करके हत्या कर दी गई 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से 6 मैतेई लोगों (तीन

महिलाएं, तीन बच्चे) को अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। इनमें से 3 के शवों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक सभी शव बहुत ही खराब हालत में थे, दो महिलाओं को तो कई बार गोली मारी गई। इन शवों में 3 साल के बच्चे चिंगखेंगनबा का शव भी था। डॉक्टरों को बच्चे के सिर में गोली का घाव मिला।

दिमाग का एक हिस्सा और दाहिनी आंख गायब थी। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे को पास से सिर में गोली मारी, जिससे उसके दिमाग का हिस्सा उड़ गया। उसके सीने और शरीर में कई जगह चाकू के घाव और हाथ में फ्रैक्चर मिला है।

एडीलेड टेस्ट के लिये टीम में बदलाव नहीं करेगा आस्ट्रेलिया

पर्थ (एजेंसी)। आस्ट्रेलिया के कोच और चयनकर्ता एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने कहा है कि पहले टेस्ट में भारत के हाथों 295 रन से हारने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा हालांकि हरमनमौला मिचेल मार्श की फिटनेस को लेकर चिंतायें हैं। मैकडोनाल्ड ने बताया कि उनकी टीम छह दिसंबर से शुरू हो रहे दिन रात के टेस्ट के लिये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से पहले ही एडीलेड पहुंचेंगी ताकि अतिरिक्त अभ्यास कर सके। उन्होंने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा ,'' पर्थ टेस्ट के लिये जो लोग चेंज रूम में थे, वही एडीलेड में भी होंगे। बदलाव करने पर हमेशा विचार होता है लेकिन हालात के अनुसार टीम चुनी जाती है।'' सितंबर में इंग्लैंड के सीमित ओवरों के दौरे के बाद से फिटनेस समस्या से जूझ रहे मार्श ने पहले टेस्ट में सिर्फ 17 ओवर डाले और तीन विकेट लिये। मैकडोनाल्ड ने कहा ,'' मुझे नहीं लगता कि पहले टेस्ट में उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। हमें उसकी फिटनेस पर नजर रखनी होगी।''

पिछली दस टेस्ट पारियों में 13 . 66 की औसत से ही रन बना सके मार्नस लाबुशेन का बचाव करते हुए उन्होंने कहा ,'' खिलाड़ियों के कैरियर के उतार चढाव पर लगातार बात होती रहती है। खराब दौर आते हैं लेकिन वह जल्दी ही फॉर्म में लौटेगा। हमें उसकी क्षमता पर यकीन है। वह ऐसा खिलाड़ी है जिसकी हमें जरूरत है।'' करारी हार के बावजूद उन्होंने कहा कि टीम का मनोबल मजबूत है।

एज टेस्ट कराने से नहीं डरते.. वैभव सूर्यवंशी के एज फॉड की खबरों पर पिता ने किया ये चैलेंज

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में करोड़ों में बिके 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही इतिहास रच दिया है। वह आईपीएल के इतिहास में बिकने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन चुके हैं। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 30 लाख के बेस प्राइस के साथ उतरे वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा। आईपीएल में करोड़ों में डील होने के बाद एक बार फिर से वैभव की उम्र पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन उनके पिता ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताया है। उनके पिता ने बताया कि वैभव का बोन टेस्ट हो चुका है और वह फिर से एज टेस्ट कारने से डरते नहीं हैं। संजीव सूर्यवंशी ने पीटीआई से कहा कि, जब वह 8.5 साल का था, तब बीसीसीआई ने पहली बार उसका बोन टेस्ट करवाया था। वह पहेल ही भारत की ओर से अंडर-19 खेल चुका है। हम किसी से डरते नहीं हैं और वह फिर से एज टेस्ट करवा सकता है। वैभव ने हाल ही में अंडर-19 टेस्ट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाया। अक्टूबर 2024 में चेन्नई के एमए चिंदबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया अंडर1-9 टीम के खिलाफ उन्होंने ये माइलस्टोन हासिल किया था। अपने पहले ही रेड बॉल मैच में उन्होंने महज 58 गेंदों पर शतक जड़ा। इसके अलावा इसी साल जनवरी में वह रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने।

संजीव ने कहा कि, वह सिर्फ अब हमारा बेटा नहीं बल्कि पूरे बिहार का बेटा है।

भारत लौटेंगे हेड कोच गौतम गंभीर

नई दिल्ली (एजेंसी)। पर्थ टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर व्यक्तिगत कारणों से मंगलवाल को ऑस्ट्रेलिया से स्वेध लौट आएंगे। 6 दिसंबर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उससे पहले ही गंभीर टीम इंडिया का फिर से ज्वाइन कर लेंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि, गंभीर ने हमें सूचित किया है कि वह स्वदेश लौटेंगे और दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया से जुड़ेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है और बोर्ड ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। भारतीय टीम पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने के लिए बुधवार को कैनबरा जाएगी। पिंक बॉल टेस्ट 6 दिसंबर से खेला जाना है। गंभीर की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम के सहायक कोच अभिषेक नायर और रेयान टेन डोशेट, गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और फील्डिंग कोच टी दिलीप कप्तान रोहित शर्मा के परामर्श से ट्रेनिंग सत्रों की देखरेख करेंगे। बता दें कि, रोहित 24 नवंबर को ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि, रोहित वॉर्म-अप मैच खेल सकते हैं।

वेंकटेश को टीम में रखना हमारी प्राथमिकता में शामिल था इसलिए पूरा जोर लगा दिया-ब्रावो

जेद्दा (एजेंसी)। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मेंटर और वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम के 'मुख्य खिलाड़ियों' को बरकरार रखने के इरादे से वेंकटेश अय्यर को अपने साथ जोड़ने के लिए 'पूरी ताकत लगाने' की टीम की रणनीति का बचाव किया है। केकेआर के लिए कप्तानी के संभावित दावेदार के रूप में देखे जाने वाले वेंकटेश को टीम के साथ जोड़ने ने आलोचनाओं को जन्म दिया है कि अगर उन्हें नेतृत्व दिया जाना टीम प्रबंधन की योजना का हिस्सा था तो उन्हें रिटेन (टीम के साथ बरकरार रखना) क्यों नहीं किया गया।

चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के साथ चार आईपीएल खिताब जीतने वाले ब्रावो ने कहा,''वैंकी (वेंकटेश अय्यर) को जोड़ना हमारे लिए मुख्य प्राथमिकताओं में से एक था, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने उसके लिए पूरा जोर लगा दिया।'' उन्होंने कहा, ''यह अच्छा है हमारे पास चैंपियनशिप

जीतने वाली टीम के 90 प्रतिशत खिलाड़ी हैं। यह अपने आप में सकारात्मक संकेत है।'' ब्रावो ने कहा, ''जब आप शुरू से टीम तैयार करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखें, संयोजन तैयार करना काफी जटिल होता है।'' भारत के लिए नौ टी20 अंतरराष्ट्रीय और दो एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय खेलने वाले मध्य प्रदेश के 29 वर्षीय ऑलराउंडर वेंकटेश को केकेआर ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा। वह सोमवार को यहां संपन्न दो दिवसीय आईपीएल नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने। सिर्फ ऋषभ पंत (लखनऊ, 27 करोड़) और श्रेयस अय्यर (पंजाब, 26.75 करोड़ रुपये) के लिए उनसे अधिक बोली लगी। ब्रावो तूफानी तेज गेंदबाज उमरान मलिक के केकेआर से जुड़ने को लेकर भी रोमांचित हैं। उन्होंने कहा, ''वह जिस गति से गेंदबाजी करता हैं, मैं हमेशा उसकी सराहना करता हूं। उसकी कड़ी मेहनत, ऊर्जा और सभी चीजें। खुशी है कि हम उसे अपने साथ जोड़ पाए।

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने खरीदे 182 खिलाड़ी

नई दिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2025 मेगा नीलामी संपन्न हो गई। इस नीलामी में कल 577 खिलाड़ियों की बोली लगी, जिनमें से सिर्फ 182 खिलाड़ी ही खरीदे गए। सभी 10 टीमों ने कुल मिलाकर नीलामी में 639.15 करोड़ रुपये खर्च किए। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस ही ऐसी टीम रहीं जिन्होंने सभी 25 स्लॉट भरे हैं। वहीं ऋषभ पंत लीग के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन पर लखनऊ ने 27 करोड़ रुपये का दांव खेला। वहीं दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपये में खरीदा।

(रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु)

लियाम लिविंगस्टोन- 8.75 करोड़ रुपये, फिल साल्ट- 11.50 करोड़ रुपये, जितेश शर्मा- 11 करोड़ रुपये, जोश हेज़लवुड - 12.5 करोड़ रुपये, रसिख डार - 6 करोड़ रुपये, सुयश शर्मा- 2.6 करोड़ रुपये, क्रुणाल पंड्या- 5.75 करोड़ रुपये, भुवनेश्वर कुमार- 10.75 करोड़ रुपये, स्वप्निल सिंह- 50 लाख रुपये, टिम डेविड- 3 करोड़ रुपये, रोमारियो शेफर्ड - 1.5 करोड़ रुपये, नुवान तुषारा - 1.6 करोड़ रुपये, मनोज भंडगे- 30 लाख रुपये, जैकब बेथेल- 2.6 करोड़ रुपये, देवदत्त पडिक्कल- 2 करोड़ रुपये, स्वास्तिक चिकारा- 30 लाख रुपये, लुंगी एनगिडी - 1 करोड़ रुपये, अभिनंदन सिंह- 30 लाख रुपये, मोहित राठी- 30 लाख रुपये

मुंबई इंडियंस

जसप्रित बुमरा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट (12.50 करोड़ रुपये), नमन धीर (5.25 करोड़ रुपये), रॉबिन मिंज (65 लाख रुपये), कर्ण शर्मा (50 लाख रुपये) , रयान रिकेल्टन (1 करोड़ रुपये), दीपक चाहर (9.25 करोड़ रुपये), अल्लाह ग़ज़नफ़र (4.80 करोड़ रुपये), विल जैक्स (5.25 करोड़ रु.), अश्वनी कुमार (30 लाख रु.), मिशेल सेंटनर (2 करोड़ रु.), रीस टॉपले (75 लाख रु.), कृष्णन श्रीजीत

(30 लाख रु.), राज अंगद बावा (रु. 30 लाख), सत्यनारायण राजू (30 लाख रुपये), बेवॉन जैकब्स (30 लाख रुपये), अर्जुन तेंदुलकर (30 लाख रुपये), लिज़ाद विलियम्स (75 लाख रु.), विग्नेश पुथुर (30 लाख रु.)

चेन्नई सुपर किंग्स

रुतुराज गायकवाड़, मथीशा पथिराना, शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी, डेवोन कॉनवे (6.25 करोड़ रुपये), राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़ रुपये), रचिन रवींद्र (4 करोड़ रुपये), आर. अश्विन (9.75 करोड़ रुपये)), खलील अहमद (4.80 करोड़ रुपये), नूर अहमद (10 करोड़ रुपये), विजय शंकर (1.20 करोड़ रुपये), सैम कुरेन (2.40 करोड़ रु.), शेख रशीद (30 लाख रु.), अंशुल कंबोज (3.40 करोड़ रु.), मुकेश चौधरी (30 लाख रु.), दीपक हुडा (1.70 करोड़ रु.), गुरजापनीत सिंह (रु. 2.20 करोड़), नाथन एलिस (2 करोड़ रुपये), जेमी ओवरटन (1.50 करोड़ रुपये), कमलेश नागरकोटी (30 लाख रु.), रामकृष्ण घोष (30 लाख रु.), श्रेयस गोपाल (30 लाख रु.), वंश बेदी (55 लाख रु.), आंद्रे सिद्दार्थ (30 लाख रु.)

राजस्थान रॉयल्स स्क्वॉड

संजू सैमसन, यशस्वी जयसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटमायर, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर (12.50 करोड़ रुपये), महेश थीक्षाना (4.4 करोड़ रुपये), वानिंदु हसरंगा (5.25 करोड़ रुपये), आकाश मधवाल (रुपये)। 1.20 करोड़), कुमार कार्तिकेय (30 लाख रु.), नितीश राणा (रु.) 4.20 करोड़ रुपये), तुषार देशपांडे (6.50 करोड़ रुपये), शुभम दुबे (80 लाख रुपये), युद्धवीर सिंह (35 लाख रुपये), फजलहक फारूकी (2 करोड़ रुपये), वैभव सूर्यवंशी (1.10 करोड़ रुपये), क्वेना मफाका (1.50 करोड़ रु.), कुणाल राठौड़ (30 लाख रु.), अशोक शर्मा (30 लाख रु.)

लखनऊ सुपर जायंट्स

निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत (27 करोड़ रुपये), डेविड मिलर (7.5 करोड़ रुपये), एडेन मार्कराम (2 करोड़ रुपये), मिशेल मार्श (3.40 करोड़ रुपये) , अवेश खान (75 लाख रुपये), प्रिंस यादव (30 लाख रुपये), युवराज चौधरी (30 लाख रुपये), राजवर्धन हंगरगेकर (30 लाख रुपये), अर्शिन कुलकर्णी (30 लाख रुपये), मैथ्यू ब्रीट्ज़के (75 लाख रुपये)।

पंजाब किंग्स

शशांक सिंह, प्रभसिमरन सिंह, अर्शदीप सिंह (18 करोड़रुपये), श्रेयस अय्यर (26.75 करोड़ रुपये), युजवेंद्र चहल (18 करोड़ रुपये), मार्कस स्टोइनिस (11 करोड़ रुपये), ग्लेन मैक्सवेल (4.20 करोड़ रुपये) , नेहल वढेरा (4.20 करोड़ रुपये), हरप्रीत बराड़ (1.50 करोड़रुपये), विष्णु विनोद (95 लाख रु.), विजयकुमार वैश्य (1.80 करोड़ रु.), यश ठाकुर (1.60 करोड़ रु.), मार्को जेनसन (7 करोड़ रु.), जोश इंग्लिस (2.60 करोड़ रु.), लॉकी फर्ग्यूसन (2 करोड़ रु.)), अज़मतुल्लाह उमरज़ई (2.40 करोड़ रुपये), हरनूर पन्नू (30 लाख रुपये), कुलदीप सेन (रु. 80 लाख), प्रियांश आर्य (3.80 करोड़रुपये), एरोन हार्डी (1.25 करोड़ रुपये), मुशीर खान (30 लाख रुपये), सूर्यांश शेडगे (30 लाख रुपये), जेवियर बार्टलेट (80 लाख रुपये), पाइला अविनाश (30 लाख रुपये), प्रवीण दुबे (30 लाख रुपये)।

मुझे लगा कि सूर्यवंशी को निखरने के लिये रॉयल्स में अच्छा माहौल मिलेगा-राहुल द्रविड़

जेद्दा (एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सत्र में उनकी टीम 13 वर्ष के वैभव रघुवंशी को निखरने के लिये अच्छा माहौल दे सकती है। बिहार के समस्तीपुर जिले के आठवीं कक्षा के छात्र सूर्यवंशी को रॉयल्स ने एक करोड़ 10 लाख रूपये में खरीदा और वह आईपीएल करार पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। द्रविड़ ने आईपीएल द्वारा जारी वीडियो में कहा ,'' मुझे लगता है कि उसमें अच्छा कौशल है और हमें लगा कि उसके विकास के लिये हम अच्छा माहौल दे सकते हैं। वह हमारे ट्रायल के लिये आया था और उसे देखकर हमें बहुत खुशी हुई।''

नीलामी में सूर्यवंशी का बेसप्राइज 30 लाख रूपये था और दिल्ली कैपिटल्स ने पहली बोली लगाई। राजस्थान ने दिल्ली को पछाड़कर इस खिलाड़ी को खरीदा। सूर्यवंशी ने हाल ही में चेन्नई में आस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के खिलाफ भारत अंडर 19 टीम के लिये युवा टेस्ट में शतक जमाया था और वह यह श्रेय हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बने।सूर्यवंशी ने उस मैच में 62 गेंद में 104 रन बनाये थे।

उन्होंने राजस्थान के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शनिवार को बिहार के लिये टी20 क्रिकेट में पदार्पण करके छह गेंद में 13 रन बनाये। जूनियर सर्किट पर चर्चा में रहे सूर्यवंशी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। उन्होंने पांच मैचों में 10 की औसत से रन बनाये हैं। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले सूर्यवंशी ने मुंबई के खिलाफ 2023 . 24 रणजी ट्रॉफी सत्र में पदार्पण किया जब आधिकारिक रिकॉर्ड में उनकी उम्र 12 वर्ष 284 दिन थी जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने।

उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बिहार के लिये वीनू मांकड़ ट्रॉफी खेलकर पांच मैचों में 400 के करीब रन बनाये थे। द्रविड़ ने कहा कि नीलामी में उनका लक्ष्य गेंदबाज थे।

अतीत के संघर्षों ने हर हालात का सामना करने का आत्मविश्वास दिया -यशस्वी जायसवाल

पर्थ नई दिल्ली (एजेंसी)। क्रिकेट खेलने का सपना पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश से 11 बरस की उम्र में ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंचे यशस्वी जायसवाल मैदान कर्मियों के साथ टेंट में रहे और रात को पानी पुरी बेचकर अपना गुजारा चलाया लेकिन अतीत के इन संघर्षों ने उन्हें मैदान के भीतर और बाहर हर लड़ाई के लिये तैयार कर दिया। कारपेट बनाने के लिये मशहूर भदोही से आस्ट्रेलिया के पर्थ तक जायसवाल का सफर उनकी लगन, प्रतिबद्धता और जिजीविषा की कहानी कहता है। इन संघर्षों से मिले अनुभव का इस्तेमाल वह मैदान के भीतर और बाहर की हर लड़ाई जीतने के लिये कर रहे हैं।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां पहले टेस्ट में शानदार शतक जमाने वाले जायसवाल को विराट कोहली के बाद भारतीय बल्लेबाजी का अगला

सितारा माना जा रहा है। जायसवाल ने आस्ट्रेलियाई टीवी प्रसारक मार्क हॉवर्ड से कहा ,'' यह ऐसी चीज है (अपनी कहानी) जो मुझे आत्मविश्वास देती है कि मैं किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। मैं हमेशा संघर्ष का सामना करने को तैयार रहता हूं। मुझे चुनौतियों का सामना करने में मजा आता है और मैं हर लड़ाई जीतना चाहता हूं।''

बाईस वर्ष के इस बल्लेबाज ने कहा ,'' इससे मैं यही सीखता हूं और मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूं कि ऐसी जिंदगी मिली जिससे मुझे खुद के बारे में सीखने का मौका और आत्मविश्वास मिला। जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करने का हौसला मिला।'' उन्होंने कहा ,'' यह अद्भुत है और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं , उसके लिये ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं वही कर रहा हूं जिससे मुझे प्यार है। मैं हर गेंद का मजा लेना चाहता हूं।''

पर्थ में पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाने के बाद दूसरी पारी में शतक पूरा होने के बाद अलग अंदाज में जश्न के बारे में पूछने पर जायसवाल ने कहा ,'' मैने अलग अंदाज में शतक पूरा किया। मैं दिमाग में कुछ और सोच रहा था और अचानक कुछ और हो गया , जिसके बाद मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं।'' उन्होंने कहा ,'' मैंने फिर सोचा , चलो ठीक है।

मैं इस पल का मजा लेता हूं। मैं भाग्यशाली हूं और यह अनुभव मेरे साथ हमेशा रहेगा। मैंने अपने सभी प्रियजनों और प्रशंसकों को चुंबन दिया। मैं इसके जरिये अपना प्यार उन तक पहुंचाना चाहता था।' उन्होंने कहा ,'' मैंने वाट्सअप पर अपने परिवार को कॉल किया और उनके साथ भी जश्न का हिस्सा बना।

ऋषभ पंत की सैलरी में होगी कटौती, 27 करोड़ में से मिलेंगे महज 19 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिके। उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं फैंस के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या, पंत को पूरे 27 करोड़ रुपये मिलेंगे? वहीं अगर वो चोटिल हो गए तो उन्हें कितनी रकम मिलेगी?

बता दें कि, ऋषभ पंत को पूरे 27 करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। दरअसल, आईपीएल 2025 की नीलामी में खिलाड़ियों पर बोली लगाई गई और फ्रेंचाइजी से उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसका मतलब है कि पंत को जिस कीमत पर खरीदा गया है वो उन्हें 3 साल की अवधि के लिए चुकाई जाएगी। पंत को 27 करोड़ में खरीदा गया है तो उन्हें ये सैलरी तीन सीजन के लिए दी जाएगी। पंत को 27 करोड़ में लखनऊ ने खरीदा है इसमें से करीब 8.1 करोड़ रुपये टैक्ट काटे जाएंगे। यानी

पंत को 3 साल के लिए स्लैब से नेट सैलरी के रूप में 18.9 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। वहीं अगर पंत को आईपीएल के दौरान चोट लगती है तो उन्हें सीजन के लिए तय की गई पूरी सैलरी मिलेगी। हालांकि, अगर टूर्नामेंट से पहले कोई चोट लगती है जिससे उनका आईपीएल में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाता है तो फ्रेंजाइजी को उनकी जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करने का अधिकार है। टूर्नामेंट से पहले चोट लगने की स्थिति में विदेशी खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। अगर कोई भारतीय खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए चोटिल हो जाता है वो आईपीएल के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसे बोर्ड की बीमा पॉलिसी के तहत पूरे सीजन की सैलरी मिलती है।

साथ ही अगर किसी भारतीय या विदेशी खिलाड़ी का आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ पूरे टूर्नामेंट के लिए अनुबंध हो, लेकिन वह एक भी मैच न खेले, तो भी वह अपनी पूरी सैलरी पाने का हकदार है। हालांकि, अघर कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत कारणों से टूर्नामेंट से हट जाता है तो उसका भुगतान खेले गए मैचों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इसी तरह, अगर कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो जाता है तो फ्रेंचाइजी को अनुबंधित पूरी राशि का भुगतान करना होगा।

कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की

प्रभार के जिलों में सप्ताह में दो दिन अनिवार्य उपस्थित रहें

सभी न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब दावा सात दिनों में दर्ज करें

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के पाँच आवेदकों से प्रतिदिन संवाद करें। जिला स्तरीय अधिकारियों से प्रतिदिन प्रकरणों के निराकरण की जानकारी लें। सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण लेबल-1 अथवा अन्य किसी स्तर पर अनअटेंडेड रहने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी जिला स्तरीय अधिकारी अपने प्रभार के नवगठित जिलों में प्रत्येक बुधवार और गुरूवार को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करें। नवगठित मैहर और मऊगंज जिलों का भ्रमण के समय संबंधित कलेक्टर को अवश्य अवगत कराएं।

कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में बड़ी संख्या में न्यायालयीन प्रकरण तथा अवमानना के प्रकरण लंबित हैं। सभी अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणों में सात दिन की समय सीमा में शत-प्रतिशत जवाब दावा दर्ज करा दें। जिन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं हैं उनमें तत्काल प्रकरण के प्रभारी की तैनाती करें। न्यायालय द्वारा पारित प्रकरणों में तत्परता से कार्यवाही करें। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रकरण लंबित हैं। न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में हर माह रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सरल भाषा में योजनाओं की जानकारी तैयार करें। इसके साथ आवेदन पत्र के प्रारूप तथा योजना से लाभ लेने की प्रक्रिया का भी उल्लेख करें। विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नवाचार के प्रयासों की आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संयुक्त संचालक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट सूची में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शामिल कराने के लिए विशेष कक्षाएं लगाएं। कमजोर विद्यार्थियों के लिए भी अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करें। अधिकारी भी स्वेच्छा से स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। कमिश्नर ने बैठक से अनुपस्थित संयुक्त संचालक शहरी विकास को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि 27 नवम्बर को कृष्णा राजकपूर ऑडिटोरियम में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सभी अधिकारी और कर्मचारी शिविर में शामिल होकर रक्तदान के पुनीत कार्य में अपना योगदान अनिवार्य रूप से दें।

बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, एसीएफ विद्याभूषण मिश्रा, उप संचालक खनिज संजीव मोहन पाण्डेय, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा, अधीक्षण यंत्री पीएचई जेएस धुर्वे, मुख्य अभियंता ऊर्जा आईके त्रिपाठी, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कथित वरिष्ठ पत्रकार का पैसे की लेन देन करते वीडियो वायरल

पत्रकारों का ठेकेदार बन करता है वसूली

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। बीते लंबे समय पत्रकारिता को कलंकित करने के प्रयास लगातार कुछ यूट्यूबरों के द्वारा किए जा रहे हैं जिसमें खबरों में अपनी सक्रियता दिखाकर कथित पत्रकारों के द्वारा शोषित और पीड़ित व्यक्तियों के साथ लूट की जाती है तथा खबर चलाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूल की जाती है। जिससे आमजनता और पिछड़े हुए लोगों को सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है मगर वसूलीबाज पत्रकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आए।

पत्रकारिता को कलंकित करता एक नया मामला हाल ही में सामने आया है जहां एक कथित पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि कथित पत्रकार के द्वारा खबर चलाने के नाम पर एक व्यक्ति से मोटी रकम वसूल की गई। जिसके बाद वह वीडियो लगातार सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है।

बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 पत्रकारों का समूह लेकर चलने वाला यह कथित पत्रकार खुद के झोले में यूट्यूब और बड़े बड़े चैनलों की करीब 10 माइक आईडी रखकर घूमता है और इन सभी पत्रकारों और चैनलों में खबर चलाने के नाम पर लोगों से रुपए लेता है जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस तथाकथित पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उक्त पत्रकार के द्वारा आए दिन अन्य पत्रकारों के नाम से खबर चलाने के नाम पर 500 - 500 रुपए की वसूली की जाती है वहीं यह पत्रकार खबरों का ठेकेदार बनकर शहर में भ्रमण करता रहता है और खुद को वरिष्ठ पत्रकार कहकर लोगों से खुद को ही संबोधित कराता है।

खाद की कालाबाजारी पर दो दुकान सील

ग्राहकों को रसीद नहीं दे रहा था दुकानदार; वीडियो आया सामने

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा में खाद की कालाबाजारी और गड़बड़ी मिलने पर मंगलवार को दो दुकानों को सील कर दिया गया। प्रशासनिक अमले ने दोनों गोदाम का भी निरीक्षण किया। बताया गया कि दुकानदार ऊंचे दाम में खाद बेच रहे थे और उसके बदले कोई रशीद तक नहीं दे रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया। इसके बाद प्रशासनिक अमले ने दबिश देकर कार्रवाई की।

जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई रीवा कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर संचालित शिव खाद बीज भंडार और सीताराम खाद बीज भंडार नाम की दुकानों पर हुई।

एसडीएम, तहसीलदार ने सील की दुकानें: शिकायत के बाद एसडीएम वैशाली जैन ने तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला, सीएसपी रितु उपाध्याय समेत प्रशासनिक अमले के साथ दोनों दुकानों पर कार्रवाई की। बता दें कि इन दिनों किसान खाद वितरण केंद्रों पर खाद पाने के लिए लंबी लाइन में लग रहे हैं। सुबह से शाम तक इंतजार के बाद भी किसान भाइयों को खाद बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। रीवा की करहिया मंडी में मौजूद खाद वितरण केंद्र में तो लोग रात 2 और 3 बजे से ही खाद पाने के लिए खाद वितरण केंद्र में लाइन लगा रहे हैं।

किसान बार-बार आरोप लगाते हुए खाद के कालाबाजारी की शिकायत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाद की कालाबाजारी की वजह से ही उन्हें समय पर खाद नहीं मिल पा रही है।

कमिश्नर कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना का हुआ वाचन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। संभाग के सभी जिलों में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाया गया। संभाग के सभी शासकीय कार्यालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया गया। कमिश्नर कार्यालय सभागार में कमिश्नर बीएस जामोद ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। अपर कमिश्नर अरूण परमार, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, सभी संभागीय अधिकारी तथा कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक रूप से वाचन किया।

इस अवसर पर कमिश्नर ने कहा कि देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉ राजेन्द्र प्रसाद ने की। इसे सहयोग देने के लिए 9 समितियाँ गठित की गईं। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ बीआर अम्बेडकर को बनाया गया। देश का संविधान 26 नवम्बर 1949 को स्वीकार किया गया। संविधान दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर इसका अमृत महोत्सव साल भर मनाया जाएगा। इसे 26 जनवरी 1950 से देश में लागू किया गया। संविधान की हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित प्रतियाँ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। देश के संविधान में रामायण, महाभारत, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर की शिक्षाओं का उल्लेख है। संविधान में सुप्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस के सुंदर चित्र भी समाहित हैं।

कमिश्नर ने कहा कि संविधान के निर्माण में मध्यप्रदेश के कई विद्वानों और राजनेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें डॉ बीआर अम्बेडकर, सेठ गोविंददास, दादा धर्माधिकारी, कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, पंडित शंभूनाथ शुक्ला, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, सीताराम जाजू, फ्रैंक एंटोनी, डॉ हरिसिंह गौर शामिल थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। संविधान सभा तथा उसकी समितियों ने विभिन्न देशों के संविधानों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समाहित कर देश की एकता, अखण्डता और विकास के उद्देश्य से नवीन संविधान का निर्माण किया। संविधान के आधार पर ही देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का संचालन हो रहा है। हर व्यक्ति को देश के संविधान के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए।

गजेन्द्र दुबे एपीएसयू रीवा की कार्यपरिषद सदस्य मनोनीत हुये

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। महामहिम राज्यपाल महोदय ने भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेन्द्र दुबे को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कार्यपरिषद सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। दुबे पूर्व मे भी कार्यपरिषद के सदस्य रह चुके है तथा वर्तमान में म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर में संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के काउन्सल नियुक्त है। अपनी नियुक्ति पर दुबे ने म0प्र0 शासन के उपमुख्यमंत्री विकास पुरूष राजेन्द्र शुक्ला एवं रीवा के लोकप्रिय सांसद जर्नादन मिश्रा तथा पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस नियुक्ति पर पूर्व विधायक सेमरिया के.पी. त्रिपाठी , अध्यक्ष नगर निगम रीवा व्यंकटेश पाण्डेय वरिष्ठ भाजपा नेता बृजेन्द्र मिश्रा (सीधी), वरिष्ठ भाजपा नेता त्रियुगीनारायण शुक्ल भगत , भाजपा जिला महामंत्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने गजेंद्र दुबे को बधाई एवं शुभकामनाये प्रेषित किया।

फ्लाइट सेवा टिकट काउंटर का उप मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा एयरपोर्ट से भोपाल की सीधी कनेक्टिविटी विंध्य क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह सेवा क्षेत्र के नागरिकों के लिए समय की बचत के साथ-साथ सुविधाजनक यात्रा का माध्यम बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र को प्रगति और विकास से जोड़ने के लिए सतत प्रयासरत है। विंध्य क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह हवाई सेवा रीवा को राज्य और देश के अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इससे व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यह क्षेत्र के सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य को देश और विदेश के पर्यटकों तक पहुंचाने में भी सहायक होगी। उप मुख्यमंत्री ने भोपाल के राजा भोज अंतरराष्ट्रीय विमानतल पर "फ्लाई बिग" कंपनी के टिकट काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने भोपाल से रीवा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट सेवा की शुरुआत करते हुए यात्रियों को बोर्डिंग पास सौंपे। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भोपाल के निदेशक रामजी अवस्थी, "फ्लाई बिग" कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनते हुए यात्रियों ने अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया।

उड़ान सेवा सप्ताह में 4 दिन रहेगी उपलब्ध: रीवा और भोपाल के बीच कंपनी की उड़ान सेवा सप्ताह में 4 दिन उपलब्ध रहेगी। भोपाल से रीवा की उड़ान मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और शुक्रवार को उपलब्ध होगी। भोपाल एयरपोर्ट से फ्लाइट सुबह 8.15 बजे प्रस्थान करेगी और रीवा एयरपोर्ट पर सुबह 10.20 बजे पहुंचेगी। रीवा से भोपाल की उड़ान सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और गुरुवार को संचालित होगी। रीवा एयरपोर्ट से यह फ्लाइट दोपहर 1.40 बजे प्रस्थान करेगी और भोपाल एयरपोर्ट पर 3.45 बजे पहुंचेगी।

"हम होंगे कामयाब" अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय "महिला सुरक्षा संवाद" में हुए शामिल डिप्टी सीएम

महिला सशक्तीकरण और नशामुक्त समाज, विकास के लिए ज़रूरी

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंते तत्र देवता" के आदर्श को साकार करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। "लाड़ली लक्ष्मी योजना," "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ," और "वन स्टॉप सेंटर" जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक पवित्र मिशन है। केवल शासकीय प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में हम होंगे कामयाब अभियान अंतर्गत राज्य स्तरीय "महिला सुरक्षा संवाद" कार्यक्रम में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गौरवशाली नेतृत्व में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ आने वाली चुनौतियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। विकास को सार्थक बनाने के लिए एकजुट होकर महिलाओं को सशक्त और समाज को सुरक्षित बनाना ज़रूरी है। समाज को नशा मुक्त बनाकर युवाओं की ऊर्जा को सही राह में लगाकर देश को विश्वगुरु बनाना है तो हम सबको मिलकर इस मिशन को सफल बनाना होगा।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण आवश्यक है। यह हमारी गौरवशाली परंपरा रही है, विकृतियों को दूर करने के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने डॉ. रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता का उल्लेख करते हुए कहा कि "समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।" उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के इस संग्राम में किसी को भी तटस्थ रहने का अधिकार नहीं है। यह लड़ाई हर व्यक्ति की है, और इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने नशे के दुष्प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा कि जेंडर आधारित हिंसा का एक बड़ा कारण नशा भी है। नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से समाज को इस बुराई से मुक्त करने के प्रयास तेज किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रयास समाज में जेंडर समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कार्यक्रम सह आयोजक स्काई सोशल के प्रयास की सराहना की।

25 नवंबर से 10 दिसंबर तक "हम होंगे कामयाब" अभियान में प्रदेशवासियों को किया जाएगा जागरूक उल्लेखनीय है कि "हम होंगे कामयाब" पखवाड़ा 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य न केवल बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है, बल्कि पुरुषों की मानसिकता में बदलाव लाकर एक नए समाज की नींव रखना भी है। पखवाड़े के दौरान विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वय से गतिविधियां निर्धारित की गई हैं। आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग सूफिया फारूकी वली, स्काई सोशल की फाउंडर सु सृष्टि प्रगट सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक/प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया ऑडीटर पब्लिकेशन प्रा.लिमि. राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय राजीव मार्ग निराला नगर रीवा से प्रकाशित, **संपादक संदीप द्विवेदी**, आर.एन.आई नं. 69082/97, डाक पंजीयन क्र.- म. प्र./ रीवा संभाग/ 46/2023-2025, प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9589645803, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।